



दिल्ली को स्वच्छ और हरित राजधानी बनाना हमारी... पृष्ठ-2

दिव्य भारत



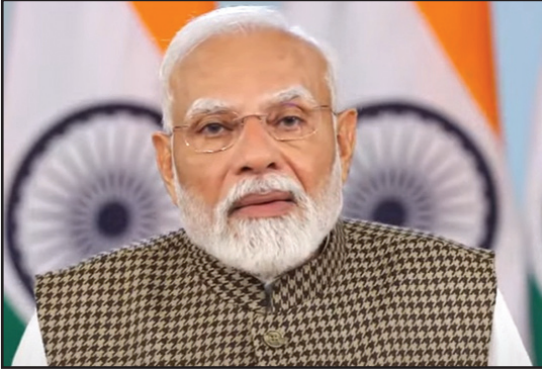
राजा भइया ने किया करोड़ों की लागत से बनने वाली सड़क... पृष्ठ-3

भारत को विकसित बनाने का पहला पड़ाव गांवों को विकसित बनाना है : मोदी

रमाकान्त पाण्डेय

भावनगर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को भावनगर जिले के बावलियाली गांव में संत श्री नगाला बापा-ठाकर धाम के पुनः प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में वीडियो संदेश से श्रद्धालुओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भरवाड समाज की गौसेवा और प्रकृति प्रेम की सराहना की। प्रधानमंत्री ने समाज के लोगों से विकसित भारत बनाने में योगदान देने की अपील की। मोदी ने कहा कि भारत को विकसित बनाने का पहला पड़ाव गांव को विकसित बनाने का है। आज प्रकृति और पशुधन सेवा हमारा सहज धर्म है।

मोदी ने कहा कि 25 वर्ष में विकसित भारत बनाना है। इसके लिए समाज की मदद जरूरी है। प्रधानमंत्री ने केन्द्र सरकार की योजना का जिक्र करते हुए कहा कि फुट एंड माउथ डिजिटल में पशुओं को लगातार वैक्सीन लेना रहता है। यह करुणा का काम है, इसे जरूर कराएं। दूसरी योजना का जिक्र कर मोदी ने कहा कि किसानों के बाद अब पशुपालकों को भी क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। इससे पशुपालकों को कम ब्याज पर बैंक से रुपये मिलेंगे। गाय के देशी नस्ल को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने पशुपालकों को इन योजनाओं का लाभ लेने को कहा। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाने,



प्रकृति खेती अपनाने आदि संबंध में भी बात की।

इससे पूर्व प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में हुए महाकुंभ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक महाकुंभ के पुण्य अवसर पर महंत रामबापु को महामंडलेश्वर की पदवी मिलना हम सभी के लिए गौरव की बात है। पिछले एक सप्ताह से भावनगर की यह धरती मानो भगवान श्रीकृष्ण की वृंदावन बन गई है। भाईजी की भागवत कथा ने इसमें सोना में सुगंध पैदा कर दिया। पूरा वातावरण भगवान श्रीकृष्ण के रस से सराबोर हो गया। बावलिया का धाम एक धार्मिक स्थान नहीं है बल्कि भरवाड समाज समेत अनेकों के लिए यह आस्था, संस्कृति और एकता की प्रतीक भूमि भी है। नगा लाखा ठाकर की कृपा से यह पवित्र स्थान हमेशा सच्ची दिशा,

उत्तम प्रेरणा का विरासत मिला है। इस धाम में नगा लाखा ठाकर की पुनःप्राण प्रतिष्ठा अनमोल अवसर पैदा करता है।

प्रधानमंत्री ने धंधुका आदि क्षेत्रों में पानी की कमी का उल्लेख कर इसु बापु के सेवा कार्य का उल्लेख किया। मोदी ने कहा कि भरवाड समाज परिश्रम, त्याग में हमेशा आगे रहा है। प्रकृति व संस्कृति का संरक्षक है। उन्होंने कहा कि अब

समाज को लकड़ी का नहीं, कलम का समाज बनाना है। नई पीढ़ी अब शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। बेटियों के हाथ में कम्प्यूटर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भरवाड समाज के लोग वृद्धाश्रम में नहीं जाते हैं। संयुक्त परिवार की प्रथा के कारण यह बुजुर्गों की सेवा को अपना नैतिक मूल्य समझता है, नई पीढ़ी भी इसे खूबो निभा रही है। मोदी ने कहा कि अभी का समय समाज को आधुनिकता के साथ जोड़ने, देश और दुनिया के साथ जोड़ने का है। बेटियों को खेलकूद में आगे लाने का प्रयास होना चाहिए। पशुपालन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ लें। मोदी ने कहा कि गिर गाय के लिए सरकार की चिंता करने का असर है कि दुनिया भर में इसे सराहना मिली है।

स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल पर साधा निशाना

नई दिल्ली, (हि.स.)। राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने पंजाब सरकार के सिंधू बार्डर पर किसानों पर बुलडोजर चलाए जाने पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह केजरीवाल के गुस्से और बदले की भावना का प्रतीक है।

स्वाति मालीवाल ने एक्स पोस्ट में लिखा कि अरविंद केजरीवाल का मकसद हाववे खुलवाना नहीं बल्कि अपने लिए राज्यसभा का रास्ता खोलना है। किसानों पर दैर रात को हुई कार्रवाई से नाराज मालीवाल ने कहा कि केजरीवाल को लगता है ऐसा करने से लुधियाना का व्यापारी खुश होगा। चुनाव जीतेंगे और अरोड़ा की राज्यसभा सीट खाली होगी।

उन्होंने कहा कि जब किसान दिल्ली में बैठे थे तो केजरीवाल ने खुद को उनका सेवादार बताया था। अब जब किसान पंजाब में बैठे हैं तो केजरीवाल ने आंदोलन को बातचीत से नहीं जोर-जुल्म से खत्म करने का प्रयास किया है। स्वाति ने सवाल किया कि ऐसा दोहरा रवैया क्यों?

अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सलमुक्त होने वाला है : शाह

नई दिल्ली, (हि.स.)। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार नक्सलियों के विरुद्ध रुथलेस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया कि अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सलमुक्त होने वाला है।

छत्तीसगढ़ में गुरुवार को दो अलग-अलग अभियानों में 22 नक्सलियों के मारे जाने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए एक पोस्ट में अमित शाह ने कहा कि नक्सलमुक्त भारत अभियान की दिशा में आज हमारे जवानों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कर्कर में सुरक्षा बलों के 2 अलग-अलग ऑपरेशन में 22 नक्सली मारे गए। मोदी सरकार नक्सलियों के विरुद्ध रुथलेस अप्रोच से आगे बढ़ रही है और समर्पण से लेकर समावेशन की तमाम सुविधाओं के बावजूद जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सलमुक्त होने वाला है।

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते वर्ष 2025 में अब तक 90 नक्सली मारे जा चुके हैं, 104 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 164 ने आत्मसमर्पण किया है। वर्ष 2024 में 290 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया था, 1090 को गिरफ्तार किया गया और 881 ने आत्मसमर्पण किया था। अभी तक कुल 15 शीर्ष नक्सली नेताओं



को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है।

बयान में कहा गया है कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच नक्सली हिंसा की कुल 16,463 घटनाएं हुई थीं, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में 2014 से 2024 के बीच नक्सली हिंसा की घटनाओं की संख्या 53 प्रतिशत घटकर 7,744 रह गई है। इसी प्रकार, सुरक्षाबल जवानों की मृत्यु की संख्या 1851 से 73 प्रतिशत घटकर 509 रह गई और नागरिकों की मृत्यु की संख्या 70 प्रतिशत की कमी के साथ 4766 से 1495 रह गई है।

मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2014 तक कुल 66 कोर्टफाइट पुलिस स्टेशन थे जबकि मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में इनकी संख्या बढ़कर 612 हो गई है। इसी प्रकार, 2014 में देश में 126 जिले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन 2024 में जिलों की संख्या घटकर मात्र 12 रह गई है। पिछले 5 वर्षों में कुल 302 नए सुरक्षा कैंप और 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड्स बनाए गए हैं।

दिशा सालियन मौत मामले को लेकर राजनीति गरमाई



मुंबई, (हि.स.)। दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा की मौत मामले को लेकर गुरुवार को महाराष्ट्र में राजनीति गरमाई गई है। इस मामले में जोरदार आरोप और प्रत्यारोपों की वजह से गुरुवार को विधानमंडल के दोनों सदनों का कामकाज कुछ देर तक के लिए स्थगित करना पड़ा। महाराज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा कि इस मामले को एसआईटी जांच चल रही है और रिपोर्ट आने पर सभागृह में पेश की जाएगी।

इस मामले को लेकर आज

सुबह सत्तापक्ष के विधायकों ने विधानभवन की सीढ़ियों पर बैठकर प्रदर्शन किया था। विधानसभा का कामकाज शुरू होने पर भाजपा विधायक अमित साठम ने कहा कि दिशा सालियन के पिता ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस मामले की एनआईए से जांच कराने की मांग की है।

दिशा सालियन ने इस मामले में शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे का नाम लिया है। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। इसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। साठम के बाद भाजपा विधायक नीतेश राणे ने भी इस मामले में आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार करने की मांग की।

इसके बाद सदन में शोरशराबा होने लगा, जिससे अध्यक्ष राहुल नावेंकर ने सभागृह का कामकाज दस मिनट के लिए स्थगित कर दिया।

पिछले एक माह में चुनाव प्रक्रिया को मजबूत बनाने को हुए साहसी प्रयास : चुनाव आयोग

नई दिल्ली, (हि.स.)। देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के रूप में कार्यभार संभाले हुए ज्ञानेश कुमार को आज एक माह पूरा हो गया। इस संबंध में आयोग ने उनके नेतृत्व में एक माह में चुनाव प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए हुए प्रयासों का ब्यौरा दिया है। आयोग का कहना है कि एक महीने के भीतर कुमार ने चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मिलकर चुनाव प्रणाली को बीएलओ स्तर तक एक मजबूत दिशा में काम किया है। इसका उद्देश्य सभी मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करना और मतदान केंद्रों पर उनके अनुभव को सुखद बनाना है।

आयोग ने एक विज्ञापित जारी कर गुरुवार को कहा कि प्रमुख हितधारक होने के नाते राजनीतिक दलों को भी जमीनी स्तर पर शामिल किया जा रहा है।

आयोग का कहना है कि यह इस बात की पुष्टि की है कि लगभग 100 करोड़ मतदाता हमेशा लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में खड़े हैं। यूआईडीएआई और ईसीआई के विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू होने वाला है। हालांकि एक मतदाता केवल निर्दिष्ट मतदान केंद्र में ही मतदान कर सकता है और कहीं और नहीं, आयोग ने ईपीआईसी नंबरों में देश भर में डुप्लिकेट को हटाने और 3 महीने के भीतर दशकों से चली आ रही समस्या को समाप्त करने



का संकल्प लिया है। मतदाता सूची को नियमित रूप से अपडेट करने के लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिकारियों के साथ समन्वय को मजबूत किया जाएगा। आयोग की राजनीतिक दलों के साथ बातचीत में यह स्पष्ट किया गया कि ड्राफ्ट निर्वाचक सूची में किसी भी समावेश या विलोपन को दावे और आपत्तियों के कानूनी प्रावधानों के तहत तय किया जाता है, जो 1950 के प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सभी राजनीतिक दलों के लिए उपलब्ध हैं। ऐसी अपीलें के अभाव में, ईआरओ द्वारा तैयार की गई सूची ही लागू मानी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि 7 मार्च, 2025 को चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया था कि 6-10 जनवरी, 2025 तक विशेष सारांश संशोधन

(एसएसआर) अभ्यास पूरा होने के बाद केवल 89 प्रथम अपील और केवल एकमात्र द्वितीय अपील दायर की गई थी।

आयोग का कहना है कि सभी पात्र नागरिकों का 100 प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना, मतदान में आसानी सुनिश्चित करना और सुखद मतदान अनुभव सुनिश्चित करना चुनाव आयोग के प्रमुख उद्देश्य हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि कोई भी मतदान केंद्र 1,200 से अधिक मतदाताओं का न हो और वे मतदाताओं के 2 किमी के भीतर हों। यहां तक कि सबसे दूरस्थ ग्रामीण मतदान केंद्रों पर भी बुनियादी सुविधाएं (एएमएफ) सुनिश्चित की जाएंगी। शहरी निष्क्रियता को दूर करने और अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, ऊंची-ऊंची इमारतों और कॉलोनियों के समूहों में भी उनके परिसर में मतदान केंद्र होंगे।

विज्ञापित में आगे कहा गया है कि लगभग 1 करोड़ चुनाव कर्मियों की व्यापक और निरंतर क्षमता निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, 4 और 5 मार्च को नई दिल्ली में आईआईआईटीएम में सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सीईओ का दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पहली बार प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के ऊपर और एफडर ने भाग लिया।

नागपुर दंगा के मास्टरमाइंड समेत 6 के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज

नागपुर, (हि.स.)। नागपुर दंगों के मास्टरमाइंड फहीम खान सहित 6 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। अब तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, एक्स और यू-ट्यूब से करीब 230 पोस्ट की पहचान की गई है। इस मामले में 50 आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और कुल 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं। शहर के 11 स्थानों पर लगाए गये कर्फ्यू में से छह स्थानों पर गुरुवार को आंशिक ढील दी गई है।

साइबर सेल के पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नागपुर में फिर से हिंसा भड़काने के लिए बेहद खतरनाक और भड़काऊ पोस्ट प्रसारित करने के आरोप में फहीम खान सहित 6 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। बतौर डीसीपी मतानी फहीम खान समेत अन्य आरोपितों



ने भड़काऊ टिप्पणियों के साथ दंगों के वीडियो वायरल करके हिंसा भड़काई। मतानी ने कहा कि 17 मार्च से अब तक फेसबुक, एक्स और यू-ट्यूब से करीब 230 पोस्ट की पहचान की गई है। इनमें से कुछ वीडियो भी शामिल हैं। इस मामले में 50 आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और कुल 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

मतानी ने बताया कि दंगों के बाद फेसबुक, एक्स और यू-ट्यूब से दोनों तरफ प्रसारित 50 फीसदी पोस्ट हटा दी गई। पोस्ट और वीडियो हटाने के लिए व्हाट्सएप और गूगल को पत्र लिखा गया है। बतौर मतानी फहीम खान ने अपना मोबाइल फोन गणेशपेट पुलिस को दे दिया है।

सेना के टी-90 टैंकों को 1350 हॉर्स पावर के इंजनों से लैस किया जाएगा

आलोक पाण्डेय

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने गुरुवार को 54 हजार करोड़ रुपये से अधिक के आठ पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने भारतीय सेना के लिए टी-90 टैंकों के इंजनों को अपग्रेड करने, नौसेना के लिए वरुणास्त्र टॉरपीडो और वायु सेना के लिए एयरबोर्न अली वॉर्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम खरीद को मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले से पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात किये गए इन टैंकों की युद्धक्षेत्र में गतिशीलता बढ़ेगी।

भारतीय सेना का प्रमुख युद्धक टैंक टी-90 रूस के टी-90 टैंक का उन्नत संस्करण है, जिसे भारत ने अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालकर 'भीष्म' नाम दिया है। सेना ने इसे चीन के साथ गतिरोध शुरू होने पर ऊंचाई



वाले क्षेत्रों में तैनात किया था, लेकिन उस समय टैंक में 1000 हॉर्स पावर के इंजन की वजह से दिक्कत आई थी। उच्च ऊंचाई पर चढ़ने में आसानी के लिए सेना ने टी-90 टैंकों में लगे 1000 हॉर्स पावर के इंजन को 1350 हॉर्स पावर के इंजनों से लैस अपग्रेड करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा था। अब आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) को हरी

झंडी मिलने के बाद टैंक के इंजनों को बदला जाएगा, जिससे युद्धक्षेत्र में गतिशीलता बढ़ेगी।

रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए वरुणास्त्र टॉरपीडो (लड़ाकू) की खरीद के लिए एओएन को भी मंजूरी दी है। नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में स्वदेशी रूप से विकसित वरुणास्त्र टॉरपीडो पनडुब्बी रोधी है। इस टॉरपीडो को अतिरिक्त मात्रा में शामिल करने से दुश्मनों की पनडुब्बी से होने वाले खतरों के खिलाफ नौसेना की क्षमता में वृद्धि होगी। जहाज से लॉन्च होने वाला टारपीडो वरुणास्त्र पहले से ही भारतीय नौसेना के पास है, लेकिन अब इस करीब 40 किलोमीटर की रेंज वाले बेहद प्रभावी हथियार की और जरूरत है। डीएसी ने आज टारपीडो की अतिरिक्त आवश्यकता के अनुरोध को मंजूरी दे दी है।

दिव्य भारत एकेडमी

UPP, UPSI, SSC, RRB Group-D, RRB NTPC

UPSSSC PET, AGNIVEER, ARMY, CTET, UPTET, STET, BANK

प्रवेश परीक्षा (B.Ed., नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल आदि)

प्रतियोगी परीक्षाओं की सम्पूर्ण तैयारी

मो: 7459096357, 7985608203

पता: बहारिया, कुण्डा-प्रतापगढ़

राजा भइया ने किया करोड़ों की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास

अजीत प्रताप सिंह/दिव्य भारत

कुंडा, प्रतापगढ़। जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कुंडा विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भइया ने गुरुवार को बिहार विकासखंड के रामनगर चौराहा बेधन गोपालपुर में करोड़ों रुपये की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। यह सड़क लालगोपालगंज से पीथीपुर होते हुए रेलवे स्टेशन बेधन गोपालपुर और मैसा चौराहा मार्ग को जोड़ेगी। 9.02 करोड़ रुपये की लागत से



बनने वाली 7.415 किलोमीटर लंबी इस सड़क को डबल लेन में चौड़ा और सुदृढ़ किया जाएगा।

राजा भइया ने मंत्रोच्चार के बीच विधिवत शिलान्यास किया और कहा कि इस सड़क के

उन्होंने यह भी कहा कि जल जीवन मिशन के पाइपलाइन कार्यों के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण की मांग मुख्यमंत्री से की गई है।

जातिवाद पर प्रहार, सामाजिक एकता पर बल

अपने संबोधन में राजा भइया ने जातिवाद के मुद्दे पर भी कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा, रमहाकुंभ में लोग देश-विदेश से आते हैं, एक साथ स्नान, भोजन और विश्राम करते हैं, फिर समाज में जातिवाद का भेदभाव क्यों? रे

निर्माण से क्षेत्रवासियों को शकरदहा, लालगोपालगंज और प्रयागराज आने-जाने में सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और क्षेत्र में सड़क निर्माण सहित अन्य विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए जातिवाद का जहर घोलकर हिंदू समाज को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन हमें अपनी आस्था को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देना है।



नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पीलीभीत टाइगर रिजर्व के वन्य जीवों और उनके संरक्षण पर केंद्रित पुस्तक भेंट करते केन्द्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद।

लैंगिक न्याय केवल एक आकांक्षा नहीं बल्कि एक संवैधानिक दायित्व : सावित्री ठाकुर

नई दिल्ली, (हि.स.)। केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने आज भारतीय विधि एवं राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महिलाओं की अनिवार्य भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने शासन और नीति-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सशक्त संस्थागत ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि लैंगिक न्याय केवल एक आकांक्षा नहीं बल्कि एक संवैधानिक दायित्व है, जिसे प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए।

केन्द्रीय राज्यमंत्री ने संसद भवन में संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान (आईसीपीएस) द्वारा आयोजित महिला, संविधान और कानून: प्रतिनिधित्व, अधिकार और सुधार विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी में ये विचार प्रकट किये। इस कार्यक्रम में नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों, वीर नारियों (युद्ध विधवाओं) और जमीनी स्तर की

महिला नेताओं ने भाग लिया और भारत के संवैधानिक एवं विधिक ढांचे में महिलाओं की बदलती भूमिका पर विचार-विमर्श किया। संगोष्ठी में महिलाओं के संवैधानिक और विधिक प्रतिनिधित्व से जुड़े तीन महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए गए।

प्रथम सत्र संविधान सभा में महिलाओं का योगदान, मौलिक अधिकारों की वकालत और संवैधानिक प्रावधानों पर उनका प्रभाव विषय पर केंद्रित था। इस सत्र की मुख्य वक्ता पूर्व केन्द्रीय महिला एवं विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने सरोजिनी नायडू, हसा मेहता और कमलादेवी चट्टोपाध्याय जैसी नेताओं के योगदान को रेखांकित किया, जिन्होंने भारतीय संविधान में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई।

द्वितीय सत्र नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण अधिनियम, 2023) का अधिकार,

प्रतिनिधित्व और उत्तरदायित्व पर केंद्रित था। इस सत्र की मुख्य वक्ता पूर्व विदेश राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी ने महिला आरक्षण अधिनियम के विधायी सफर और इसके राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर पड़ने वाले प्रभावों पर गहन चर्चा की।

तृतीय सत्र जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व और चुनौतियाँ और संभावनाएँ पर आधारित था, जिसमें पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा की गई। इस सत्र की वक्ताओं में सांसद कमलजीत सहारावत, भक्ति शर्मा (सरपंच, बरखेड़ी अब्दुल्ला) और नीरू यादव (सरपंच, लंबी अहीर) शामिल रहें।

वक्ताओं ने महिला नेताओं के सामने आने वाली संस्थागत बाधाओं, संसाधनों की कमी, और सामाजिक चुनौतियों को उजागर किया और महिला नेतृत्व को सशक्त बनाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, विधिक साक्षरता अभियानों और

परामर्श नेटवर्क की आवश्यकता पर बल दिया।

संगोष्ठी में 180 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें वीर नारियाँ (युद्ध विधवाएँ), ग्राम पंचायत और शहरी निकायों के प्रतिनिधि, विभिन्न विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्य, शोधार्थी, छात्र और मंत्रालयों के अधिकारी शामिल थे। इस विविध भागीदारी ने शासन में लैंगिक न्याय को सुदृढ़ करने की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाया।

इस संगोष्ठी ने महिला प्रतिनिधित्व, विधिक अधिकारों और शासन सुधारों पर सार्थक चर्चा के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान किया।

इसने भारत के संवैधानिक ढांचे में लैंगिक न्याय को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता को पुनः पुष्टि की, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाएँ देश के विधिक और राजनीतिक भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँ।

हर की पौड़ी पर गूँजा वेदों का मंगलस्वर : 62वें अखिल भारतीय शास्त्रोत्सव ने रचा नया इतिहास

हरिद्वार, (हि.स.)। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 62वें अखिल भारतीय शास्त्रोत्सव के अंतर्गत, पतंजलि विश्वविद्यालय की मेजबानी में विश्वप्रसिद्ध हर की पौड़ी पर भव्य आयोजन में सामूहिक रूप से शास्त्रों के श्रावण के बीच हुई भव्य गंगा आरती ने एक विश्व कीर्तिमान रच दिया।

गुरुवार को संध्याकाल में सम्पन्न यह केवल एक साधारण आध्यात्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक क्षण था, जब देश के कोने-कोने से पहुंचे हजारों विद्वानों और श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से शास्त्रों का श्रावण किया और एक साथ गंगा आरती में भाग लेकर एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की ऋचाएँ, उपनिषदों के श्लोक, भगवद्गीता के संदेश और योगसूत्रों के गूढ़ वचन-यह सब मिलकर एक ऐसा

दिव्य महासंगीत प्रस्तुत कर रहे थे, जिसमें अध्यात्म, दर्शन और भक्ति की त्रिवेणी का संगम स्पष्ट झलक रहा था। शास्त्र श्रावण के उपरांत, जैसे ही गंगा आरती का शुभारंभ हुआ, पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं गंगा माता अपने भक्तों की श्रद्धा को स्वीकार कर रही हों। यह आयोजन केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि हमारी जड़ों की ओर लौटने का एक प्रयास था। इससे यह सिद्ध हुआ कि भारतीय सभ्यता आज भी वेदों की ऋचाओं, योग की साधना, और आयुर्वेद के ज्ञान के साथ विश्व को मार्गदर्शन दे सकती है।

इस अवसर पर पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति स्वामी रामदेव ने कहा कि शास्त्र केवल शब्द नहीं, यह अमृत ज्ञान है। जब तक भारत अपनी संस्कृति और सनातन परंपरा को अपनाएगा, तब तक विश्व में

आध्यात्मिकता और शांति का प्रवाह बना रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने सनातन का उदघोष करते हुए समर्थ और संगठन होकर विकसित भारत बनाने की बात कही।

पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति और आचार्य बालकृष्ण ने संध्या आरती और शास्त्र श्रावण को विशेष बताते हुए सनातन धर्म को जीवन में उतारने की बात कही। उन्होंने आगे कहा कि वेद और शास्त्र केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है।

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के कुलपति श्री. गीर्णवास वरखेड़ी ने पतंजलि विश्वविद्यालय की इस पहल को विश्व कीर्तिमान बताते हुए कहा कि आज हजारों छात्रों ने एक साथ शास्त्र रामदेव ने कहा कि शास्त्र केवल शब्द नहीं, यह अमृत ज्ञान है। जब तक भारत अपनी संस्कृति और सनातन परंपरा को अपनाएगा, तब तक विश्व में



उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) ने गुरुवार को नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार भेंट की।

इटारसी-बुदनी-खातेगांव होकर बनाई जा रही नई रेल लाइन

भोपाल, (हि.स.)। मध्य प्रदेश के जबलपुर से इंदौर का रेल सफर आने वाले समय में पांच घंटे में पूरा होगा। ऐसा इटारसी-बुदनी-खातेगांव होकर बनाई जा रही नई रेल लाइन से संभव होगा। यह जानकारी गुरुवार को जनसम्पर्क अधिकारी देवेंद्र ओगरे ने दी।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जबलपुर से इंदौर के बीच नई रेल लाइन गाडवारा-बुदनी होकर नहीं इटारसी-बुदनी-खातेगांव होकर बनाई जा रही है। यह लाइन इंदौर-देवास रेल लाइन में मांगलिया गांव के पास जुड़ेगी। इस रास्ते में भोपाल नहीं पड़ेगा। इस नई लाइन के बनने के बाद जबलपुर से इंदौर के बीच सफर आसान हो जाएगा। इससे जबलपुर और इंदौर के बीच की दूरी 150 किलोमीटर तक कम हो जाएगी और जबलपुर से इंदौर आने-जाने में दो घंटे का समय बचेगा। उन्होंने बताया कि रेल अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में नर्मदापुरम के सांसद दर्शन सिंह चौधरी द्वारा

पूछे गए सवाल के जवाब में जबलपुर से इंदौर (वाया गाडवारा एवं बुधनी) तक बनने वाली 342 किलोमीटर लंबी रेल

लाइन परियोजना की वर्तमान स्थिति और प्रगति के बारे में जानकारी दी। रेल मंत्री वैष्णव ने बताया कि इंदौर (मांगलियागांव) और बुदनी के बीच (205 किलोमीटर) नई रेल लाइन के लिए 3261.82 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। मार्च-2024 तक इस परियोजना के लिए 948.37 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं तथा वर्ष 2024-25 के लिए इस परियोजना के लिए 1107.25 करोड़ रुपये का परिचय्य आवंटित किया गया है। गाडवारा और बुधनी के बीच (137 किमी) काम आगे नहीं बढ़ाया जाना तर्क संगत नहीं है, क्योंकि गाडवारा से बुधनी दोनों पहले से ही मौजूद नेटवर्क के माध्यम से वाया इटारसी से जुड़े हुए हैं और दोनों स्थानों के बीच दूरी में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं है। इसलिए केवल इंदौर (मांगलियागांव) और बुदनी के बीच नई रेल लाइन परियोजना पर कार्य प्रगति पर है।

उन्होंने बताया कि इस परियोजना से इंदौर से मुंबई और दक्षिण भारत के यात्रा समय में कमी आएगी। भोपाल और इटारसी के व्यस्त मार्ग (घाट सेक्सन : बुधनी से बरखेड़ा) को बायपास कर बुधनी को इंदौर से सीधे जोड़ा

जाएगा। यह रेल लाइन बुधनी के मौजूदा यार्ड से शुरू होकर इंदौर के पास पश्चिम रेलवे के मांगलियागांव स्टेशन से जुड़ेगी। रेल लाइन सीहोर, देवास एवं इंदौर जिलों को जोड़ेगी। यह रेललाइन भेरूदा, खातेगांव और कनौद जैसे कस्बों/गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जहां वर्तमान में कोई रेल संपर्क नहीं है। इस परियोजना से औद्योगिक विकास, सामाजिक-आर्थिक, रोजगार सृजन और बेहतर परिवहन सुविधाओं के माध्यम से इस क्षेत्र का समग्र विकास होगा। इधर, रेल मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के मालवा अंचल को भी इंदौर-मनमाडू नई रेल लाइन परियोजना की एक बड़ी सौगात दी है। इस परियोजना के तहत प्रदेश के तीन जिलों के 77 गांव से होकर रेल लाइन गुजरेगी। इसके लिए नवंबर 2024 में रेल मंत्रालय ने इन गांवों की जमीन अधिग्रहण के लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। इसके बाद मंत्रालय ने महु तहसील के 18 गांव की सूची भी जारी की। हालांकि, गांवों की सूची जारी होने के दो माह बाद भी जमीन अधिग्रहण का काम शुरू नहीं हो पाया है। इस संबंध में रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि रेल मंत्रालय द्वारा

14 जनवरी को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार महु तहसील के खेड़ी, चैनपुरा, कमदपुर, खुदापुरा, कुराड़ाखेड़ी, अहिल्यापुर, नदिड, जामली, केलोद, बेरख, गवली पालिसिया, आशापुरा, मलेंडी, कोदरिया, बोरखेड़ी, चौरडिया, न्यू गुराडिया, और महु कंटोमेंट एरिया की चिह्नित जमीन का रेल प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहण होना है। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

भाजपा ने अपने लोकसभा सदस्यों के लिए जारी किया ह्विप

नई दिल्ली, (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार (21 मार्च) के लिए अपने लोकसभा सदस्यों को तीन लाइन का ह्विप जारी किया है। पार्टी ने अपने सदस्यों से बजट पारित होने के लिए सदन में उपस्थित रहने को कहा है। लोकसभा कल गिलोटीन का प्रयोग करेगी। गिलोटीन लागू करने का स्पीकर को विशेषाधिकार होता है। संसदीय परंपरा में गिलोटीन भी हर समय लागू नहीं किया जाता है, बल्कि महत्वपूर्ण मौकों पर ही इसे लागू किया जाता है।

देवेंद्र फडणवीस और बिल गेट्स के बीच महाराष्ट्र के विकास पर हुई चर्चा

मुंबई, (हि.स.)। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक, प्रसिद्ध उद्यमी बिल गेट्स के बीच गुरुवार को महाराष्ट्र के विकास पर सकारात्मक चर्चा हुई। गेट्स फाउंडेशन ने महाराष्ट्र को मलेरिया मुक्त करने के लिए काम करने और 25 लाख महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र को सहयोग देने का वादा किया है।

माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स और गेट्स फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को सहाय्यी राज्य अतिथि गृह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस मुलाकात में बिल गेट्स और मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के बारे में सकारात्मक चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और बुनियादी ढांचे, कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी परियोजनाएँ चल रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी के कारण गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने बिल गेट्स से ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रभावित उपलब्ध कराने की पेशकश की है।

हालांकि बजट में स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग का भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि किसानों को दिन में बिजली मिले और इसके लिए 2022-23 से सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। किसानों को कम लागत पर बिजली मिल रही है, क्योंकि सौर ऊर्जा से अब 30 प्रतिशत बिजली उत्पादन में से 52 प्रतिशत बिजली पैदा हो रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सभी बिजली फीडरों को सौर ऊर्जा से संचालित करने की योजना है, ताकि उन्हें 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा सके। फडणवीस ने इससे संबंधित जानकारी बिल गेट्स को दी और उन्हें इस क्षेत्र में सहयोग देने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि नवी मुंबई में 300 एकड़ क्षेत्र में इन्वोवेशन सिटी बनाई जा रही है। इस पर गेट्स ने इन्वोवेशन सिटी और अन्य पहलों में वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता सहित साझेदारी करने का वचन दिया। इसके साथ ही महाराष्ट्र में मच्छरों के कारण मलेरिया से पीड़ित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र को मलेरिया मुक्त बनाने

के साथ-साथ गेट्स फाउंडेशन ड्रग पर नियंत्रण के लिए भी काम कर रहा है। बिल गेट्स ने आवासन दिया कि इसके लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी और इसकी शुरुआत गहचिरोली जिले से होगी।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार के लिए 25 लाख महिलाओं को करोड़पति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह प्रदान कर रही है। बिल गेट्स ने यह भी कहा कि माइक्रोसॉफ्ट और गेट्स फाउंडेशन भी इस पहल में भाग लेने के लिए तैयार हैं। गेट्स ने महिलाओं के सम्पूर्ण वित्तीय लेन-देन को डिजिटल बनाने में सहयोग करने की अपनी तत्परता व्यक्त की।

इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खडगे, प्रमुख सचिव अरविंद भिडे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, गेट्स फाउंडेशन के भारत निदेशक हरि मेनन, गेट्स फाउंडेशन के वैश्विक मलेरिया परियोजना निदेशक फिलिप वेल्कॉफ, स्वास्थ्य सलाहकार डॉ. आनंद बंग आदि उपस्थित थे।



पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16वें वित्त आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक करते।

उपायुक्त ने राजौरी में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की

दिव्य भारत संवाददाता

राजौरी। जिले में सड़क सुरक्षा की समीक्षा और सुदृढ़ीकरण के लिए, उपायुक्त अभिषेक शर्मा ने आज जिला सड़क सुरक्षा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। शुरूआत में, जिला रोलआउट प्रबंधक पंकज सभरवाल ने एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (आई-आरएडी) और इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) पर एक व्यापक प्रस्तुति दी। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं का विश्लेषण करने और निवारक उपाय तैयार करने में आई-आरएडी वेब पोर्टल के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सड़क वर्गीकरण और महीनेवार रुझानों के आधार पर घटनाओं को वर्गीकृत करते हुए दुर्घटना के आंकड़े प्रस्तुत किए।

यह पता चला कि जुलाई 2022 से जिले में 840 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं, सभी मामलों को दस्तावेज किया गया है और आगे

के विश्लेषण के लिए आई-आरएडी प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया है। बैठक में जागरूकता अभियान, दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट की पहचान और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्रैश बैरियर लगाने पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया गया।

उपायुक्त अभिषेक शर्मा ने दुर्घटनाओं, चोटों और मौतों को कम करने में जन जागरूकता और जिम्मेदार ड्राइविंग व्यवहार के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने सभी हितधारक विभागों से सड़क उपयोगकर्ताओं के बीच आपसी सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने का आग्रह किया और ड्राइवों को सुरक्षा सावधानियों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया। सख्त प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए, डिप्टी कमिश्नर ने यातायात और मोटर वाहन विभाग को यातायात उल्लंघन के खिलाफ विशेष अभियान चलाने और उल्लंघन करने वालों पर सख्त जुमाना लगाने का निर्देश दिया।

बैठक जिले में सड़क सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ संपन्न हुई। बैठक के दौरान चर्चा की गई पहलों को सभी नागरिकों के लिए सड़क यात्रा को सुरक्षित और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए तत्परता से लागू किया जाएगा। बैठक में एडीडीसी डॉ. राज कुमार थापा, एसई पीडब्ल्यूडी (आर एंड बी) देवी दयाल, सीपीओ मकसूद अहमद, एआरटीओ राजेश गुप्ता, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी (आर एंड बी) राजौरी, ओसी बीआरओ 58 आरसीसी ऑफिकर उनीयाल, सीईओ शिक्षा इकबाल हुसैन, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी (आर एंड बी) कालाकोट मोहम्मद आफताब, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी (आर एंड बी) थापागंडी राजेश गुप्ता, एक्सईएन पीडीडी राजौरी मोहम्मद राशिद, एक्सईएन पीएमजीएसवाई राजौरी राशिद उपस्थित थे। मुस्तफा, एक्सईएन पीएमजीएसवाई बुद्धल इमतिआज मीर और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल थे।



उपराज्यपाल लखनऊ में प्रसिद्ध लेखक श्रीलाल शुक्ल की जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुए।

उपराज्यपाल लखनऊ में प्रसिद्ध लेखक श्रीलाल शुक्ल की जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुए

दिव्य भारत संवाददाता

जम्मू। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रसिद्ध लेखक श्रीलाल शुक्ल की जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुए। श्रीलाल शुक्ल को श्रद्धांजलि देते हुए उपराज्यपाल ने श्रीलाल शुक्ल के जीवन और कालजयी कार्यों तथा ग्रामीण भारत के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की उनकी गहरी समझ पर प्रकाश डाला। उपराज्यपाल ने कहा कि श्रीलाल शुक्ल के ज्ञान, उनके विचार, उनकी कल्पना, उनके व्यंग्य की शक्ति न केवल हमारा मनोरंजन करती है, बल्कि हमें आत्मनिर्भर गांवों और विकसित भारत के निर्माण के लिए मार्गदर्शन भी करती है। सैकड़ों वर्षों में एक बार, कुछ ही लेखक अस्तित्व द्वारा उपलब्ध कराए गए ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। श्रीलाल शुक्ल उनमें से एक थे। उनका लेखन वास्तव में पथ का प्रकाश है। श्रीलाल शुक्ल की रचनाओं में जीवन के रहस्य और रोजमर्रा की जिंदगी के अंतरंग अनुभव समाहित हैं। मेरा मानना है कि उनके अनुभव से ओतप्रोत उनके शब्द शाश्वत हैं। विशेषकर राग दरबारी हमारी चेतना में समाहित हो गई है, उपराज्यपाल ने कहा। उपराज्यपाल ने समाज में सकारात्मक बदलाव

लाने के लिए श्रीलाल शुक्ल जैसे महान लेखकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उपराज्यपाल ने कहा, पुस्तकें शक्तिशाली आंतरिक आंखों की तरह होती हैं जो ज्ञान और बुद्धि की दुनिया की झलक प्रदान करती हैं। लेखक अपनी वर्णमाला के माध्यम से हमें सोचने और अपने दृष्टिकोण को बड़ा करने का अवसर देते हैं और ये लेखन संज्ञानात्मक अंतर्दृष्टि का स्रोत हैं। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों और कहानियों ने उस अवधि के दौरान समाज को प्रबुद्ध करने का काम किया है और उनके विचार हमें हमारी विकास यात्रा में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की चेतावनी देते हैं और मेरा मानना है कि उनके शब्द किसी भी अन्य प्रस्तुति से अधिक शक्तिशाली हैं। इस अवसर पर सहकारिता राज्य मंत्री श्री जेपीएस राठौर, इफको के अध्यक्ष श्री दिलीप संधानी और इफको के प्रबंध निदेशक डॉ. यू.एस. अवस्थी ने भी बात की और श्रीलाल शुक्ल को श्रद्धांजलि दी। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी और अशोक पाठक ने श्रीलाल शुक्ल की प्रसिद्ध कृति राग दरबारी का एक अंश सुनाया। श्रीलाल शुक्ल की श्रद्धेय स्मृति में आयोजित एक प्रदर्शनी का भी उपराज्यपाल ने उद्घाटन किया।

जिला चुनाव अधिकारी ने रामबन में राजनीतिक दलों से बातचीत की

दिव्य भारत संवाददाता

रामबन। रामबन में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) बसीर-उल-हक चौधरी ने राजनीतिक दलों के जिला स्तरीय प्रतिनिधियों के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया। बैठक का उद्देश्य भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के निर्देशों के अनुरूप कानूनी ढांचे के भीतर चुनावी तंत्र को मजबूत करने में सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देना था।

बैठक के दौरान डीईओ ने राजनीतिक प्रतिनिधियों को चुनावी भागीदारी और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ईसीआई की चल रही पहलों से अवगत कराया। उन्होंने इस बात

पर जोर दिया कि राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया में प्रमुख हितधारक हैं, जैसा कि आयोग ने पहचाना है और उन्हें सहभागिता के लिए इस मंच का सक्रिय रूप से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने सुझाव संरचित और लिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी चिंताओं और सिफारिशों पर उचित विचार किया जाए।

बैठक के दौरान, राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने विभिन्न मुद्दे उठाए और अपने सुझाव साझा किए, जिन पर राहन चर्चा की गई। बैठक ने चुनावी चिंताओं को दूर करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने वाले तरीके से प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया।



उपायुक्त ने राजौरी में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की।

डीसी ने राजौरी दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा की

दिव्य भारत संवाददाता

राजौरी। डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने आज पीडब्ल्यूडी डाकबंगला के कॉन्फ्रेंस हॉल में आगामी 13 अप्रैल को होने वाले राजौरी दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक के दौरान, कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई ताकि इसका सुचारू और सफल निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। जिले की समृद्ध संस्कृति और पर्यटन क्षमता को उजागर करने के लिए कई गतिविधियों की योजना बनाई गई है। इनमें सरकारी योजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल, प्रमुख पर्यटन स्थलों का प्रदर्शन और खेल आयोजन शामिल हैं।

कार्यक्रम से पहले एक प्रमुख गतिविधि टैलेट हट प्रोग्राम होगा, जिसमें स्कूल, जूनल और जिला स्तर पर गायन, संगीत,

नृत्य और मिमिक्री की प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। स्कूल शिक्षा और संस्कृति विभागों को इन प्रतियोगिताओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें शीर्ष तीन छात्रों को मुख्य कार्यक्रम में प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा, जागरूकता पहल के तहत किसानों को कीटनाशकों से निपटने के बारे में जागरूक किया जाएगा। समारोह में क्षेत्र की विविध परंपराओं को प्रदर्शित करने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा।

स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने के लिए रक्तदान शिविर और एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा, आपदा प्रबंधन के लिए एक मॉक ड्रिल अभ्यास और नशीली दवाओं के दुरुपयोग और मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएंगे।

जिले में कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को

बढ़ावा देने के लिए, राजौरी विकास प्राधिकरण को मुख्य कार्यक्रम में समर्पित स्टॉल लगाने का निर्देश दिया गया है। ये स्टॉल जिले की पर्यटन क्षमता को उजागर करेंगे और आगंतुकों को इसके दर्शनीय और ऐतिहासिक स्थलों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

इसके अतिरिक्त, ट्रेकिंग और साइकिलिंग फ्लैग-ऑफ समारोह का हिस्सा होगा। उपायुक्त ने कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों के बीच निर्बाध समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को कुशलतापूर्वक और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में एडीडीसी डॉ. राज कुमार थापा, जीएम डीआईसी फरीद कोहली, सीपीओ मकसूद अहमद, एसीपी शेरजान चौहान, डीपीओ मोहम्मद नवाज चौधरी, डीएसएचओ पी.पी. उपस्थित थे।

सिविल सोसाइटी राजौरी ने नशीली दवाओं की लत से निपटने पर सेमिनार आयोजित किया

दिव्य भारत संवाददाता

राजौरी। सिविल सोसाइटी राजौरी ने आज डाक बंगले में नशीली दवाओं की लत की बढ़ती हुई चिंताजनक स्थिति और समाज पर इसके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक सेमिनार आयोजित किया। डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य मादक द्रव्यों के सेवन से निपटने और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रभाव रणनीतियों की खोज करना था। सेमिनार के दौरान, नशीली दवाओं की लत से निपटने के लिए आवश्यक उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें सामुदायिक जागरूकता, प्रारंभिक हस्तक्षेप और पुनर्वास सहायता पर जोर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने पहल करने के लिए सिविल सोसाइटी राजौरी की सराहना की और इस बढ़ती चिंता को दूर करने में माता-पिता, शिक्षकों और स्थानीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

नशीली दवाओं के सेवन से लड़ने के लिए प्रशसन की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए, डीसी ने पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया और प्रभावित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास, जागरूकता और निवारक शिक्षा प्रदान करने के लिए बहु-हितधारक दृष्टिकोण का आह्वान किया।

राजौरी में स्वरोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की

दिव्य भारत संवाददाता

राजौरी। जिला विकास आयुक्त राजौरी अभिषेक शर्मा ने आज यहां पीडब्ल्यूडी डाकबंगला के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें बैंकों के प्रदर्शन का आकलन किया गया और जिले में प्रमुख सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।

डीडीसी ने ऋण से जुड़ी योजनाओं के तहत मामलों के निपटान की व्यापक समीक्षा की और बैंकों को आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। क्रेडिट डिफॉल्ट (सीडी) अनुपात में सुधार की आवश्यकता पर जोर देते हुए, जो वर्तमान में 55 प्रतिशत है, उन्होंने वित्तीय संस्थानों से अपनी पहुंच और ऋण देने की क्षमता बढ़ाने का आग्रह किया।

बैठक का मुख्य फोकस पशुपालन, भेड़पालन और मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के कार्यान्वयन पर था। डीडीसी ने इन क्षेत्रों में लगे किसानों और उद्यमियों को लाभ पहुंचाने के लिए संवितरण प्रक्रिया में तेजी लाने के महत्व पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना की समीक्षा करते हुए, यह पाया गया कि 719 प्रायोजित मामलों में से 272 मामलों में सफलतापूर्वक राशि वितरित की गई।

डीडीसी ने समग्र कृषि विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) के तहत कम वितरण दर पर चिंता व्यक्त की और तत्काल सुधारात्मक व्यापक करने का आह्वान किया। इसी तरह, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमजीपी) के तहत 719 प्रायोजित मामलों में से 272 का वितरण किया गया, जबकि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के तहत 126 मामलों में से 62 का वितरण किया गया। मुमकिन, तेजस्विनी, उद्यमिता को बढ़ावा, आरएसईटीआई, एनआरएलएम और पीएम सूर्य पर मुफ्त बिजली योजना सहित अन्य प्रमुख योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। डीडीसी ने अधिकारियों को अधिकतम जन भागीदारी सुनिश्चित करने और इन योजनाओं के तहत वित्तीय लाभों तक आसान पहुंच की सुविधा के लिए जागरूकता अभियान तेज करने का निर्देश दिया।

मिशन वात्सल्य योजना के तहत 27 अनाथ बच्चों को वित्तीय लाभ मिला

दिव्य भारत संवाददाता

पुंछ। पुंछ के डिप्टी कमिश्नर विकास कुंडल ने मिशन वात्सल्य योजना के तहत अनाथ बच्चों को प्रायोजन चेक वितरित करके अपना समर्थन दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन बच्चों को उनकी शिक्षा और पोषण में सहायता के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करके उनके जीवन को बेहतर बनाना था।

आज कुल 27 अनाथ बच्चों को प्रायोजन भुगतान प्राप्त हुआ, जिससे कुल 215 बच्चे इस पहल से लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम के दौरान, प्राप्तकर्ताओं के बीच 2,12,000 की प्रभावशाली राशि वितरित की गई।

उपायुक्त ने बच्चों के साथ बातचीत की और योजना के तहत प्रदान की गई सहायता का उपयोग

करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने उन्हें इस पहल से पूरा लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि यह उनकी शिक्षा और पोषण को बढ़ाने के लिए बनाया गया है, जो अंततः उनके भविष्य को उज्ज्वल करेगा। समाज कल्याण अधिकारी वकील अहमद भट ने मिशन वात्सल्य योजना के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को 18 वर्ष या 36 महीने की आयु तक, जो भी पहले हो, 4,000 रुपये की मासिक सहायता प्राप्त होगी, जिससे उनका कल्याण और भविष्य की संभावनाएं सुरक्षित होंगी।

उन्होंने सभी पात्र बच्चों से अपने जीवन स्तर और भविष्य के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से लाभ उठाने का आग्रह किया।



मिशन वात्सल्य योजना के तहत 27 अनाथ बच्चों को वित्तीय लाभ मिला।

पुंछ में कैपेक्स बजट क्रियान्वयन की समीक्षा की गई

दिव्य भारत संवाददाता

पुंछ। जिला विकास आयुक्त पुंछ विकास कुंडल ने डीसी कार्यालय परिसर के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक में जिला कैपेक्स बजट 2024-25 के तहत शुरू की गई परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न पहलों के व्यापक मूल्यांकन के लिए कार्यान्वयन विभागों के अधिकारी एकत्र हुए। मुख्य योजना अधिकारी और कार्यकारी ईजीनियरों ने विस्तृत प्रस्तुतियां दीं, जिसमें बीडीसी, डीडीसी और पीआरआई क्षेत्र विकास अनुदान के तहत परियोजनाओं की क्षेत्रवार स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। ग्रामीण विकास, जल शक्ति, शिक्षा, जेपीडीसीएल, नगर पालिका, स्वास्थ्य क्षेत्रों के तहत गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें निर्मित बनाम अनिर्मित

परियोजनाओं के व्यय और प्रगति पर विशेष ध्यान दिया गया। खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) ने वस्तुअल रूप से भाग लिया, अपने-अपने ब्लॉकवार कार्यों पर व्यापक अपडेट पेश करते हुए लंबित परियोजनाओं के समय पर निष्पादन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्हें परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने का निर्देश दिया गया।

उपायुक्त ने विभिन्न योजनाओं में निधि के अधिकतम उपयोग की आवश्यकता पर जोर देते हुए सभी विभागों और क्रियान्वयन एजेंसियों से वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रयास तेज करने का आह्वान किया। बैठक में जिले के विकास उद्देश्यों को बिना देरी के हासिल करने के लिए सहयोग और जवाबदेही के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित किया गया।

रूस-यूक्रेन ने रिहा किए सैकड़ों लोग, संघर्ष विराम की दिशा में बड़ा कदम

कीव/मॉस्को, (हि.स.)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को रोकने के प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। रूस ने यूक्रेन के 175 और यूक्रेन ने रूस के इतने ही कैद किए गए लोगों को रिहा कर दिया। इसे ट्रंप की संघर्ष विराम की कोशिश की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दोनों देशों के अपने समकक्षों से फोन पर वार्ता कर चुके हैं।

यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेन्स्की ने एक्स पर 24 घंटे पहले की गई पोस्ट में कहा कि आज बड़ा दिन है। रूस ने हमारे 175 रक्षकों को कैद से रिहा कर दिया है। अन्य 22 रक्षक आदान-प्रदान से गैर उपायों के माध्यम से घर लौट रहे हैं। उनमें गंभीर रूप से घायल योद्धा और वह लोग शामिल हैं जिन्हें रूस ने मनगढ़ंत अपराधों के लिए सताया। इन सभी को तुरंत आवश्यक चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जेलेन्स्की ने

इस जानकारी के साथ कुछ फोटो भी अपलोड किए हैं। जेलेन्स्की ने इसके लिए संयुक्त अरब अमीरात का भी आभार जताया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अपने सभी नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए प्रतिबद्ध है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने 19 मार्च को कहा कि मॉस्को और कीव ने कैदियों की अदला-बदली की है। इनमें रूस के 175 और यूक्रेन के 175 कैदी शामिल हैं। सद्भावना के तौर पर रूस ने यूक्रेन को 22 गंभीर रूप से घायल युद्धबंदियों को भी सौंप दिया। इस अदला-बदली की घोषणा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान की। उल्लेखनीय है कि यूक्रेन की कैद से रिहा लोगों का फोटो तास ने रूस के रक्षा मंत्रालय के सौजन्य से जारी किया है।

जेलेन्स्की ने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में दावा किया यूक्रेन पर रूस के हमले बंद नहीं हो रहे।

हर दिन और हर रात लगभग सौ या उससे ज्यादा ड्रोन हमले हो रहे हैं। इससे दुनिया के सामने मॉस्को का असल चेहरा सामने आ रहा है। कल रात रूस ने लगभग 200 ड्रोन हमले किए। इन हमलों के दौरान किरोवोह्राद क्षेत्र के चार बच्चों सहित 10 लोग घायल हो गए। कई घरों, एक चर्च और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा।

तास के अनुसार, यूक्रेन में अमेरिका की युद्ध विराम की कोशिशों के बीच रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि यूरोप सैन्यीकरण में ढूँढ गया है। यह मॉस्को और वाशिंगटन की शांतिपूर्ण समाधान के प्रति प्रतिबद्धता के बिल्कुल विपरीत है। इस घटनाक्रम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेन्स्की के साथ फोन पर अपनी हालिया बातचीत को बहुत अच्छा बताया है। ट्रंप ने विश्वास जताया है कि जल्द ही रक्तपात रोकने पर एक समझौता हो जाएगा।



यूक्रेन में एक अज्ञात स्थल पर राष्ट्रीय झंडे के साथ नजर आ रहे युद्ध बंदी। युद्ध बंदियों की अदला-बदली के बाद इनकी वापसी हुई है।

अमेरिका की इजराइल की नीति का विरोध करने पर भारतीय शोधकर्ता हिरासत में

वाशिंगटन, (हि.स.)। अमेरिका में जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के एक भारतीय शोधकर्ता को संघीय आतंजन अधिकारियों ने हिरासत में लिया है। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में छात्र वीजा पर अध्ययन और अध्यापन कर रहे बदर खान सूरी को सोमवार रात वर्जीनिया के अल्लेंटन के रॉसलिन में उनके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया।

डिजिटल अखबार पॉलिटिको की खबर के अनुसार, सूरी पर अमेरिका की इजराइली विदेश नीति का विरोध करने का आरोप लगाया गया है। उनके वकील हसन अहमद ने मुवक्किल की तत्काल रिहाई के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में कहा गया है कि अधिकारियों ने खुद को होमलैंड सिक्योरिटी विभाग से संबद्ध बताया। उन्होंने सूरी को बताया कि सरकार ने उनका वीजा रद्द कर दिया है।

वकील अहमद ने याचिका में तर्क दिया कि सूरी को उनकी पत्नी की

फिलिस्तीनी विरासत के कारण दंडित किया जा रहा है। सूरी की पत्नी मफेज सालेह अमेरिकी नागरिक हैं। सरकार को सदेह है कि वह और उनकी पत्नी इजराइल के प्रति अमेरिकी विदेश नीति का विरोध करते हैं। साथ ही कुछ वेबसाइटों पर मफेज सालेह के हमास के साथ संबंध होने का आरोप लगाया गया है। वह अल जजीरा के लिए काम कर चुकी हैं।

'पॉलिटिको' ने अपनी खबर में भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में इस जोड़े के बारे में 2018 में प्रकाशित एक लेख का जिक्र किया है। इस लेख के अनुसार, मफेज सालेह के पिता अहमद यूसुफ हमास के शीर्ष नेतृत्व के वरिष्ठ राजनीतिक सलाहकार रह चुके हैं। उधर, होमलैंड सुरक्षा विभाग की प्रवक्ता ट्रिसिया मैकलॉघलिन ने पुष्टि की कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शनिवार को एक आदेश जारी किया कि विदेश नीति कारणों से सूरी का वीजा रद्द कर दिया जाना चाहिए।

प्रवक्ता ने एक्स पर लिखा, सूरी

जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में एक विदेशी विनियम छात्र था जो सक्रिय रूप से हमास का प्रचार कर रहा था और सोशल मीडिया पर यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा दे रहा था। सूरी के एक ज्ञात या सदिग्ध आतंकवादी से घनिष्ठ संबंध हैं, जो हमास का वरिष्ठ सलाहकार है।

इस बीच वकील अहमद ने कहा कि बुधवार शाम तक वह सूरी से संपर्क नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि सूरी का मुकदमा मंगलवार को वर्जीनिया के अलेक्जेंड्रिया में संघीय अदालत में दायर किया गया। पॉलिटिको ने अदालत से सूरी की याचिका की प्रति प्राप्त की है। बुधवार शाम तक सूरी के मामले में किसी न्यायाधीश को नियुक्त नहीं किया गया था और अदालत ने इस पर कोई कार्यवाई नहीं की थी।

जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, सूरी अलवलीद बिन तलाल सेंटर फॉर मुस्लिम-क्रिस्चियन अंडरस्टैंडिंग में पोस्टडॉक्टरल फेलो

हैं। यह विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विस का हिस्सा है। वह दक्षिण एशिया में बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यक अधिकार पर पढ़ा रहे हैं। सूरी ने भारत के एक विश्वविद्यालय से 'शांति और संघर्ष' विषय पर पीएचडी की है। इस बारे में एक अन्य भारतीय न्यूज चैनल की खबर में साफ किया गया कि उन्होंने दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया के नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन से पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज में 2020 में पीएचडी पूरी की।

यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता के अनुसार, डॉ. खान सूरी भारतीय नागरिक हैं। उन्हें इराक और अफगानिस्तान में शांति स्थापना पर अपने डॉक्टरेट शोध को जारी रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने के लिए विधिवत वीजा दिया गया। हमें उनके किसी अवैध गतिविधि में शामिल होने की जानकारी नहीं है और हमें उनकी हिरासत का कोई कारण नहीं बताया गया है।

पाकिस्तान की हुकूमत पर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री का तंज, कहा-विज्ञप्तियों से नहीं खत्म होगा आतंकवाद

इस्लामाबाद, (हि.स.)। पाकिस्तान के लंबे समय से अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने आतंकवाद के मुद्दे पर संघीय सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विज्ञप्तियों से आतंकवाद कभी नहीं खत्म होगा। अगर ऐसा होता तो जाने कब पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म हो जाता। उन्होंने आतंकवाद से लड़ने का संकल्प लेने वाले शीर्ष नागरिक-सैन्य दल की कड़ी आलोचना की और तर्क दिया कि केवल बैठक करने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

पाकिस्तान के द न्यूज इंटरनेशनल अखबार की खबर के मुताबिक, एक स्थानीय टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में मुख्यमंत्री गंडापुर ने कहा कि अगर आतंकवाद को केवल एक विज्ञप्ति जारी करने या एक बैठक करने से खत्म किया जा सकता, तो यह अब तक खत्म हो चुका होता। उन्होंने सुझाव दिया कि देश

से आतंकवाद को खत्म करने की रणनीति तैयार करने के लिए एक समिति गठित की जानी चाहिए।

उनकी यह टिप्पणी आतंकवाद को पूरी ताकत से हराने के लिए एकता और राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर जोर दिए जाने के एक दिन बाद आई पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म हो जाता। उन्होंने आतंकवाद से लड़ने का संकल्प लेने वाले शीर्ष नागरिक-सैन्य दल की कड़ी आलोचना की और तर्क दिया कि केवल बैठक करने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

पाकिस्तान के द न्यूज इंटरनेशनल अखबार की खबर के मुताबिक, एक स्थानीय टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में मुख्यमंत्री गंडापुर ने कहा कि अगर आतंकवाद को केवल एक विज्ञप्ति जारी करने या एक बैठक करने से खत्म किया जा सकता, तो यह अब तक खत्म हो चुका होता। उन्होंने सुझाव दिया कि देश

में बैठक से दूरी बनाकर रखी। यह बैठक जाफर एक्सप्रेस पर आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर बुलाई गई थी।

इस बैठक में सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने कठोर रुख अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर कब तक देश 'नरम राज्य' के नाम पर अनगिनत बलिदान देता रहेगा।

मुख्यमंत्री गंडापुर ने कहा कि पीटीआई के नेतृत्व वाली सरकार प्रांत में किसी भी ऑपरेशन की अनुमति नहीं देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा कि पहले भी ऑपरेशन किए गए हैं, लेकिन वह फायदेमंद नहीं रहे हैं। इसके बजाय उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। गंडापुर ने कहा कि केवल आतंकवादियों को मारना समाधान नहीं है। आतंकवादियों को पनाह देने वालों का चेहरा भी बेनकाब करना होगा।



गाजा में फिलिस्तीनी लोग अपने घरों से भागते हुए। इजरायली सेना की चेतावनी के बाद ये लोग अपने घरों से भागते दिख रहे हैं।

फिनलैंड के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खुश

वाशिंगटन, (हि.स.)। समूची दुनिया में फिनलैंड के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबीइंग रिसर्च सेंटर की प्रकाशित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट-2025 के अनुसार, फिनलैंड ने लगातार आठवें साल खुशहाल देशों की सूची में प्रथम स्थान हासिल किया है। डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन भी शीर्ष 10 में शामिल हैं। यह रिपोर्ट गैलप, वेलबीइंग रिसर्च सेंटर, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की मेहनत का नतीजा है।

सीएनबीसी न्यूज चैनल के अनुसार, गैलप की प्रबंध निदेशक इलाना रॉन लेवे ने कहा कि नॉर्डिक देशों का इस सूची में शीर्ष पर होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिनलैंड के लोग अपने जीवन के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि नॉर्डिक शब्द का मतलब है उत्तरी यूरोप और खास तौर पर स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र। नॉर्डिक शब्द की उत्पत्ति स्थानीय शब्द 'नॉर्डेन' से हुई है। इसका मतलब है 'उत्तर'। आमतौर पर नॉर्डिक शब्द का इस्तेमाल

बाल्टिक सागर के आसपास के यूरोप के उत्तरी क्षेत्र के लिए किया जाता है।

रॉन लेवे ने कहा कि सूची तैयार करने में रिपोर्ट में शामिल 130 से अधिक देशों की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार से मुक्ति के प्रयासों का ध्यान रखा गया। लेवे का मानना है कि एक और फिनलैंड को अन्य देशों से अलग रखती है। वह है परोपकारी कार्यों का महत्व। वह कहती है कि परोपकार करने से खुशी को भी बढ़ावा मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष 10 की सूची में जगह बनाने में विफल रहा और वास्तव में पिछले साल 23वें स्थान से गिरकर 24वें स्थान पर आ गया। रॉन लेवे ने कहा कि अमेरिकी अकेले भोजन करने में अधिक से अधिक समय बिता रहे हैं।

वह कहती है कि खुशी का मतलब सिर्फ जीडीपी या उच्च वेतन से नहीं बल्कि विश्वास, सामाजिक संबंध, रिश्ते और इन सभी अलग-अलग आयामों से है। यही बात सबसे ज्यादा खुश देशों को अलग करती है। उन्होंने कहा कि कोस्टा रिका और मेक्सिको दोनों पहली बार शीर्ष 10 पर पहुंचे हैं। इससे

पता चलता है कि लोगों को खुश करने के लिए आपको दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक होने की जरूरत नहीं है। बुनियादी आर्थिक जरूरतें पूरी होने पर उच्च जीवन मूल्यांकन भी संभव है।

वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट-2025 की सूची में शीर्ष देशों में क्रमशः फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नोर्दलैंड, कोस्टा रिका, नॉर्वे, इजराइल, लक्जमबर्ग और मेक्सिको हैं। डेनमार्क 2025 के लिए दुनिया का दूसरा सबसे खुशहाल देश है। यह एक दशक से ज्यादा समय से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में शीर्ष 10 में रहा है। रॉन लेवे कहती हैं कि हालांकि डेनमार्क के लोग दुनिया के सबसे ज्यादा करों में से कुछ का ही भुगतान करते हैं। देश में अधिकतर स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त हैं। बच्चों की देखभाल पर सब्सिडी दी जाती है। विश्वविद्यालय के छात्र पढ़ाई के दौरान खर्चों को पूरा करने के लिए अनुदान प्राप्त करते हैं। बुजुर्गों को पेंशन मिलती है और उन्हें देखभाल करने वाले सहायक उपलब्ध कराए जाते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन बेहतर जीवन सुचकांक के अनुसार, नॉर्डिक देश नौकरियों, शिक्षा,

स्वास्थ्य, पर्यावरण गुणवत्ता, सामाजिक संबंधों, नागरिक जुड़ाव और जीवन संतुष्टि में औसत से बेहतर प्रदर्शन करता है। डेनमार्क इस संगठन और नाटो का संस्थापक सदस्य है।

अफगानिस्तान (नंबर 147) एक बार फिर सूची में सबसे नीचे है। सिएरा लियोन (नंबर 146), लेबनान (नंबर 145), मलावी (नंबर 144) और जिम्बाब्वे (नंबर 143) खुशहाली के मामले में सबसे निचले पांच देशों में शामिल हैं।

पोप फ्रांसिस की स्थिति में सुधार, वेंटिलेटर से हटाया गया

वेटिकन सिटी, (हि.स.)। लंबे समय से अस्वस्थ पोप फ्रांसिस की स्थिति में आशाजनक सुधार हुआ है। उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। अब वह आराम से सांस ले रहे हैं। होली सी प्रेस कार्यालय ने पोप फ्रांसिस के स्वास्थ्य पर बुधवार शाम जारी अपडेट में यह जानकारी दी। वेटिकन न्यूज के अनुसार, स्वास्थ्य बुलेटिन में कहा गया है कि पोप स्थिति में अप्रत्यूष सुधार की पुष्टि हुई है।

इजराइल के ताजा जमीनी हमले में हमास के छह आतंकी मारे गए, अब तक 500 की मौत

गाजा पट्टी, (हि.स.)। इजराइल की गाजा पट्टी में आतंकी समूह हमास के खिलाफ शुरू की गई जमीनी लड़ाई में कम से कम नौ लोग मारे गए। इनमें छह आतंकी शामिल हैं। मंगलवार को युद्ध विराम टूटने के बाद से अब तक इजराइल के हवाई और जमीनी हमले में कम से कम 500 लोग मारे गए हैं। इजराइल की थल सेना ने आज सुबह उत्तरी गाजा के बेत लाहिया में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया।

सीएनएन की खबर के अनुसार, इजराइली सुरक्षा बलों (आईडीएफ) ने कहा कि बेत लाहिया में उसके ताजा हमले में छह आतंकवादियों को मार दिया गया। यह ड्रोन हमले का प्रयास कर रहे थे। मारे गए हमास के आतंकवादियों में एक सात अक्टूबर के हमले में शामिल रहा है। आईडीएफ के दावे विपरीत ब्रिटेन में पंजीकृत एनजीओ अल-खैर फाउंडेशन ने कहा कि इस इस हमले में आठ चैरिटी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इस संगठन के संस्थापक कासिम रशीद अहमद ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि यह फाउंडेशन और दुनिया

भर के मानवीय कार्यकर्ताओं के लिए दुःखद दिन है।

इस बीच हमास के मीडिया कार्यालय के महानिदेशक इस्माइल थवाब्ना ने इजराइल पर बेत लाहिया में नरसंहार करने का आरोप लगाया है। हमास ने कहा कि अगर युद्ध विराम को बढ़ाया जाता है तो वह अमेरिकी-इजराइली सैनिक एडन अलेक्जेंडर और गाजा में बंधक बनाए गए चार दोहरी नागरिकता वाले लोगों के शव लौटा देगा।

इस बीच इजराइल की सेना ने आज सुबह यमन के हूती विद्रोहियों की दागी गई मिसाइल को रोक दिया। हूती ने गाजा में युद्ध विराम के टूटने के बाद इजराइल को दूसरी बार मिसाइल दागकर निशाना बनाया है। अमेरिका ने ईरान समर्थित उग्रवादी समूह हूती के खिलाफ हवाई हमले तेज कर दिए हैं। हूती ने कहा है कि यह बैलिस्टिक मिसाइल हमला फिलिस्तीनियों के समर्थन में किया गया। इजराइली रक्षा बलों (आईडीएफ) के अनुसार, मिसाइल को इजराइली क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही रोक

दिया गया था। इस पर हूती ने कहा कि मिसाइल ने बेन गुरियन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया। यह हवाई अड्डा तेल अवीव के बाहरी इलाके में इजराइल का मुख्य विमानन केंद्र है।

नेपाल सरकार ने भारत से पीक ऑवर में मांगी 230 मेगावाट बिजली

काठमांडू, (हि.स.)। नेपाल सरकार ने भारतीय दूतावास के जरिए भारत सरकार से पीक ऑवर में 230 मेगावाट बिजली आपूर्ति करने का अनुरोध किया है। इस समय नेपाल 8-10 घंटे तक बिजली की कटौती का सामना कर रहा है, जिससे देश के उद्योग कल कारखानों के उत्पादन में भारी कमी आई है।

नेपाल के ऊर्जा मंत्री दीपक खड्का ने गुरुवार को संसद की प्रतिनिधि सभा में सांसदों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के जरिए अतिरिक्त बिजली आपूर्ति के लिए भारत सरकार से औपचारिक अनुरोध किया गया है।



सना में अमेरिकी हमले के बाद इलाके में जमा लोग।

मुख्यमंत्री नीतीश ने सेपक टाकरा वर्ल्ड कप-2025 का किया शुभारंभ

पटना, (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पाटलिपुत्र खेल परिसर, कंकड़बाग में सेपक टाकरा वर्ल्ड कप- 2025 के शुभारंभ की घोषणा कर इस खेल प्रतियोगिता की औपचारिक शुरुआत की।

मुख्यमंत्री ने खिलाड़ी एवं आयोजकों के साथ सेपक टाकरा वर्ल्ड कप के सामने तस्वीर भी खिंचवाई।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनायें दी और उपस्थित लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। बिहार में पहली बार सेपक टाकरा वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में विश्व के 20 देशों के 300 से अधिक खिलाड़ी और प्रशिक्षक हिस्सा लेंगे। 20 से 25 मार्च तक पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में इसका आयोजन किया जा रहा है।

इस खेल का अंतरराष्ट्रीय स्तर का आयोजन कर बिहार ने नया इतिहास रचा है। यह बिहार

के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण है। इस आयोजन से न केवल बिहार को वैश्विक खेल मंच पर एक नई पहचान मिलेगी बल्कि राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी और अंतराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं व प्रतिस्पर्धा का अनुभव होगा।

सेपक टाकरा दक्षिण-पूर्व एशिया का एक पारंपरिक खेल है, जिसमें खिलाड़ी बांस से बनी एक विशेष गेंद (सेपक) को पैरों, सिर, घुटनों और छाती की मदद से खेलते हैं। इसे फुटबॉल और वॉलीबॉल का मिश्रण कहा जा सकता है, जिसमें खिलाड़ी को अधिक लचीलापन, संतुलन और कौशल की आवश्यकता होती है। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और म्यांमार जैसे देशों में यह खेल अत्यंत लोकप्रिय है। अब बिहार इस खेल के माध्यम से वैश्विक खेल मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए

तैयार है। कार्यक्रम के दौरान इंटरनेशनल सेपक टाकरा फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल दातुक अब्दुल हलीम कादिर ने मुख्यमंत्री को प्रतीक चिह्न भेंटकर सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने बिहार के सेपकटाकरा खिलाड़ी बाँबी कुमार को प्रतीक चिह्न भेंटकर सम्मानित किया।

कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक डॉ रविंद्रन शंकरण, खेल विभाग के निदेशक महेंद्र कुमार, इंटरनेशनल सेपक टाकरा फेडरेशन के अध्यक्ष बुन चाई लोर पीपथ, इंटरनेशनल सेपक टाकरा फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल दातुक अब्दुल हलीम कादिर, सेपक टाकरा फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह दहिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रशिक्षक एवं प्रतिभागी देशों के खिलाड़ी उपस्थित थे।



ब्राजील में विश्वकप फुटबॉल के कोनमीबोल क्वालीफायर मुकाबले में कोच डोरिवेल जूनियर खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए।



मियामी ओपन टेनिस में ब्रिटेन की इमा राडूकानो फोरहैंड शॉट लगाती हुई।

खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का भव्य उद्घाटन, 1300 से अधिक पैरा एथलीट लेंगे भाग

नई दिल्ली, (हि.स.)। केन्द्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर स्थित केडी जाधव इंडोर हॉल में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दूसरे संस्करण का औपचारिक उद्घाटन किया। यह प्रतिष्ठित आयोजन आठ दिनों तक चलेगा, जिसमें छह प्रमुख खेलों में 1300 से अधिक पैरा एथलीट अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

इस अवसर पर केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार भी उपस्थित रहे। खेलों की शुरुआत एक विशेष मशाल रेली के साथ हुई, जिसमें छह प्रतिष्ठित पैरालिंपियन झा सिमरन शर्मा (एथलेटिक्स), प्रवीण कुमार (बैडमिंटन), नितेश कुमार (बैडमिंटन), नित्या श्री (बैडमिंटन) और प्रीति पाल (एथलेटिक्स) ने भाग लिया। इनके साथ भारतीय पैरालिंपिक समिति के अध्यक्ष और पूर्व पैरालिंपियन देवेन्द्र झाझरिया तथा अरुणाचल प्रदेश के खेल और युवा मामलों के मंत्री केटी जिनी भी उपस्थित रहे।

डॉ मंडाविया ने कहा, जब कोई इंसान शारीरिक रूप से कमजोर होता है, तो परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स हमारे एथलीटों के लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, जिससे उन्हें बेहतरीन अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने पेरिस पैरालिंपिक 2024 में भारत द्वारा 29 पदकों की ऐतिहासिक उपलब्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय पैरा एथलीट

अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश को गौरवान्वित कर रहे हैं।

खेल मंत्री ने कहा, खेलो इंडिया इवेंट अब देश के उन एथलीटों के लिए सबसे उपयुक्त प्लेटफॉर्म बन गया है, जो वैश्विक स्तर पर भारत के लिए पदक जीतने की इच्छा रखते हैं। चाहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स या खेलो इंडिया पैरा गेम्स हों, भारतीय खिलाड़ी हर जगह अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं।

केन्द्रीय मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 न केवल एथलीटों के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक मंच है, बल्कि यह उनकी प्रेरणादायक यात्रा को उजागर करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर भी प्रदान करता है।

इस उद्घाटन समारोह में देशभर के एथलीट, कोच, सहयोगी कर्मचारी और खेल प्रशासक शामिल हुए। इसके अलावा, खेल मंत्रालय की सचिव सुजाता चतुर्वेदी और भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

इस वर्ष खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, व्हीलचेयर बास्केटबॉल, पैरा स्विमिंग, पैरा टेबल टेनिस और पैरा पावरलिफ्टिंग जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इन खेलों के माध्यम से युवा पैरा एथलीटों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर

मिलेगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का यह संस्करण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खेलो इंडियाखेलों और आगे बढ़ो विजन को साकार कर रहा है और देश में खेल संस्कृति को और अधिक समृद्ध बना रहा है।

भारतीय सेना ने गुज्जर और बक्करवालों के लिए वॉलीबॉल मैच किया आयोजित

रियासी, (हि.स.)। स्थानीय समुदायों के बीच सद्भाव, जुड़ाव और खेल भावना को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयास में भारतीय सेना ने शिकारी जिला रियासी के सुदूर स्थान पर गुज्जर और बक्करवाल समुदायों के लिए एक दोस्ताना वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय युवाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई जिन्होंने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना से अपनी खेल भावना और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस पहल का उद्देश्य शारीरिक फिटनेस और टीम वर्क को बढ़ावा देते हुए भारतीय सेना और स्थानीय आबादी के बीच के बंधन को मजबूत करना था। सेना के अधिकारियों ने प्रतिभागियों से बातचीत की और एकता और अनुशासन को बढ़ावा देने में खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला। समुदाय के सदस्यों ने इस तरह के आउटरीच कार्यक्रमों के आयोजन में भारतीय सेना के निरंतर प्रयासों की सराहना की जो क्षेत्र में शांति और विकास में योगदान करते हैं।

दिल्ली

एलआईसी ने राहुल गांधी के दावों का किया खंडन

नई दिल्ली, (हि.स.)। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने गुरुवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दावों का खंडन करते हुए कहा कि वह अपने पॉलिसीधारकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और अपने सभी एजेंट के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

एलआईसी की ओर से यह स्पष्टीकरण एलआईसी एजेंट्स के एक प्रतिनिधिमंडल का राहुल गांधी से मुलाकात करने और भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) तथा एलआईसी द्वारा नियमों में हाल ही में किए गए बदलावों का मुद्दा उठाने के एक दिन बाद आया है। एलआईसी एजेंट ने नेता विपक्ष से कहा था कि इरडा तथा एलआईसी द्वारा किए गए नियमों में बदलाव से गरीब तथा वंचित समुदायों के लिए

बीमा कम किफायती हो गया है तथा एजेंट की स्थिति कमजोर हो गई है। एलआईसी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं प्रबंध निदेशक (एमडी) सिद्धार्थ मोहंती ने एक बयान में कहा, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि एलआईसी द्वारा ऐसे उत्पाद बाजार में प्रस्तुत किए गए हैं, जो इरडा द्वारा निर्धारित नए उत्पाद विनियमों के अनुरूप हैं। यह एक अक्टूबर, 2024 से प्रभावी हैं, जिसमें पॉलिसीधारकों के हितों को सर्वोपरि रखा गया है।

मोहंती ने कहा कि एलआईसी जीवन बीमा कवरेज को व्यापक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने लगातार ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक एवं सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित किया है। हमारा उद्देश्य हर बीमा योग्य व्यक्ति

को सस्ती कीमत पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। उन्होंने कहा, एलआईसी का विविध पोर्टफोलियो हर प्रकार के ग्राहक और समाज के विभिन्न स्तरों की सेवा के साथ-साथ सभी नियामक आवश्यकताओं का पूरी तरह से अनुपालन करता है।

उन्होंने कहा कि उदाहरण के तौर पर एलआईसी की सूक्ष्म बचत योजना न्यूनतम एक लाख रुपये की बीमा राशि प्रदान करती है और यह माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से मुक्त है, जिससे इसकी पहुंच सुनिश्चित होती है। मोहंती ने जोर देकर कहा कि उत्पाद नियमों में बदलाव के बाद एजेंट के लिए कमीशन कम नहीं किया गया है, बल्कि इसे चरणबद्ध तरीके से दिया गया है। उन्होंने कहा, एलआईसी अपने पॉलिसीधारकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित है,

साथ ही अपनी एजेंसी से जुड़े लोगों की भलाई का भी समर्थन करती है।

उल्लेखनीय है कि बुधवार को राहुल गांधी ने एलआईसी एजेंट के एक प्रतिनिधिमंडल से उनके संसद भवन कार्यालय में मुलाकात करने के बाद कहा था कि वह ईरडा और एलआईसी के द्वारा नियमों में बदलाव किए जाने से संबंधित एलआईसी एजेंट की चिंताओं को संसद में उठाएंगे। उन्होंने कहा था, जब 1956 में एलआईसी का गठन किया गया था, तो इसका उद्देश्य सभी भारतीयों को किफायती बीमा प्रदान करना था, विशेष रूप से सबसे गरीब लोगों को जिनके पास कोई अन्य सामाजिक सुरक्षा नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा उठाऊंगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एलआईसी का समावेशी दृष्टिकोण सुरक्षित रहे।



नई दिल्ली। ओबीसी कर्मचारी कल्याण संघों के राष्ट्रीय परिसंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से संसद भवन नई दिल्ली में मुलाकात की।



नई दिल्ली। समर एक्शन प्लान के तहत साप्ताहिक समीक्षा बैठके, स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर।

समर एक्शन प्लान के तहत साप्ताहिक समीक्षा बैठके, स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने समर एक्शन प्लान के तहत नई पहल शुरू की है, जिसके तहत अब हर साप्ताहिक दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठके हो रही हैं। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य जल आपूर्ति को सुचारु बनाना, सीवर व्यवस्था को सुधारना और जल वितरण में पारदर्शिता बढ़ाना है। इस पहल का लक्ष्य गर्मी के मौसम में दिल्लीवासियों को स्वच्छ पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना, अवैध जल कनेक्शनों पर रोक लगाना और तंत्र में हो रहे नुकसान को रोकना है।

गुरुवार की बैठक में पिछले साप्ताहिक किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और अगले साप्ताहिक के लिए कार्ययोजना तैयार की गई। अधिकारियों को जल आपूर्ति प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने, लीकेज रोकने, सीवर जल को समस्याओं का समाधान करने और समग्र जल वितरण को सुधारने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। इसके अलावा, जल प्रबंधन में

जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की गई।

प्रवेश वर्मा ने जल कनेक्शनों को कानूनी रूप से मान्य बनाने और उन्हें जनता के लिए अधिक सुलभ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल जल कनेक्शन की दरें बहुत अधिक हैं, जिससे लोग अवैध कनेक्शनों की ओर बढ़ते हैं। हम इन दरों की समीक्षा करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग कानूनी रूप से जल कनेक्शन ले सकें। हम एक समय सीमा निर्धारित करेंगे, जिसके बाद अवैध रूप से जल उपभोग करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

जल आपूर्ति की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जल मंत्री ने घोषणा की कि जीपीएस से लैस टैंकरों के लिए नया ट्रैकिंग जारी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय टैंकरों की आवाजाही और उनके जल आपूर्ति बिंदुओं का कोई सटीक रिकॉर्ड नहीं है। मैंने निर्देश दिया है कि प्रत्येक टैंकर को जीपीएस से लैस किया जाए और जल

वितरण स्थलों की सूची बनाकर उचित दस्तावेजीकरण किया जाए। इसके साथ ही, गर्मी के मौसम में जल आपूर्ति को और अधिक मजबूत करने के लिए टैंकरों की ट्रिप संख्या बढ़ाकर 16 प्रति दिन कर दी जाएगी।

इसके अलावा वर्मा ने अंडरग्राउंड जलाशयों से होने वाले जल प्रवाह की निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि राजस्व और नुकसान का सही आकलन किया जा सके। उन्होंने कहा कि ये सभी कदम जल आपूर्ति प्रणाली को बेहतर बनाने, जल की बर्बादी रोकने और दिल्ली जल बोर्ड द्वारा संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने में मदद करेंगे।

उन्होंने कहा कि समर एक्शन प्लान के तहत साप्ताहिक बैठकों के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि दिल्ली के हर नागरिक को निर्बाध जल आपूर्ति मिले। इन सुधारों से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, जिससे अंततः दिल्ली की जनता को सीधा लाभ मिलेगा।

आईपी यूनिवर्सिटी ने शुरू की एडमिशन चैटबॉट सेवा

नई दिल्ली, (हि.स.)। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (आईपीयू), द्वारका ने नए सत्र के विभिन्न प्रोग्राम में दाखिले से जुड़े सवालों का त्वरित जवाब देने के लिए एडमिशन चैटबॉट सेवा की शुरुआत की है। इस सेवा की शुरुआत पर यूनिवर्सिटी के कुलपति पद्मश्री प्रो. (डॉ.) महेश वर्मा ने कहा कि आवेदकों की सुविधा को ध्यान में रखकर इस सेवा की शुरुआत की गई है। यूनिवर्सिटी की दाखिला प्रक्रिया के निदेशक प्रो. उदयन घोष ने बताया कि एआई आधारित यह ऑनलाइन सेवा नए सत्र में दाखिले से संबंधित हर संभावित प्रश्नों के अत्यंत त्वरित गति से सटीक उत्तर देने में सक्षम है। इसका लिंक यूनिवर्सिटी की मुख्य वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस सेवा का उपयोग कर नए सत्र के विभिन्न प्रोग्राम में दाखिले से संबंधित प्रश्नों का तत्काल उत्तर पाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि आईपी यूनिवर्सिटी के सभी प्रोग्राम में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च है। ऐसे में दाखिले से जुड़े किसी सवाल का जवाब आसानी से इस चैटबॉट से पाया जा सकता है।

पांच साल तक छात्राओं का यौन शोषण करने का आरोपी प्रोफेसर गिरफ्तार

हाथरस, (हि.स.)। छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर डा. रजनीश कुमार को पुलिस और एसओजी ने प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया। वह सात दिन से हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर स्टे के लिए भागदौड़ कर रहा था। आरोप है कि डा. रजनीश पिछले पांच साल से कालेज की छात्राओं का यौन शोषण कर रहा था। मामला उत्तर प्रदेश के हाथरस के बागला डिग्री कॉलेज का है। आरोप है कि कालेज का असिस्टेंट प्रोफेसर डा. रजनीश कुमार 30 से ज्यादा छात्राओं का यौन शोषण कर चुका है। 150 वर्षीय प्रोफेसर छात्राओं को पास करने और नौकरी लगवाने का झांसा देकर ऑफिस में बुलाकर उनके साथ अश्लील हरकतें करता था। चोरी-छिपे वीडियो भी बना लेता था। प्रोफेसर के मोबाइल से 65 अश्लील वीडियो मिले हैं। ज्यादातर वीडियो कॉलेज की

छात्राओं के हैं। कुछ वीडियो उसने पोर्न साइट पर भी अपलोड किए हैं। आरोपी प्रोफेसर 20 साल से बागला डिग्री कॉलेज में तैनात है। वह भूगोल पढ़ाता है। एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने पुलिस लाईंस में पत्रकार वार्ता में बताया कि छह मार्च को एक छात्रा ने राज्य महिला आयोग को गोपनीय लेटर लिखा था। उसमें 'डा. रजनीश की सभी कारगुजारियों का कच्चा चिट्ठा लिखते हुए फोटो-वीडियो भी भेजे थे। छात्रा के पत्र का महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए। इसके बाद हाथरस गेट कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू की और प्रोफेसर को पूछताछ के लिए बुलाया। उसके मोबाइल को कब्जे में ले लिया, लेकिन उसने पहले ही वीडियो-फोटो डिलीट कर दिए थे। पुलिस ने मोबाइल का डेटा रिकवर कराया तो 65 अश्लील वीडियो मिले।

विदेशी आक्रांता के महिमामंडन का मतलब देशद्रोह, ऐसे देशद्रोही स्वीकार नहीं : योगी

आलोक पाण्डेय/दिव्य भारत
बहराइच/लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बहराइच में विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन करने वालों को देशद्रोही करार दिया।

उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की सनातन संस्कृति और परंपरा का गुणगान कर रही है तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। इन स्थितियों में किसी भी आक्रांता का महिमामंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता के महिमामंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना है और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है।

उन्होंने कहा कि जो लोग भारत के महापुरुषों को अपमानित करते हों, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करते हों जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने और हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का यह नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है।

- विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन और भारतीय महापुरुषों का अपमान करने वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दो टूक
- जिन्होंने सनातन संस्कृति, बेटियों की इज्जत और हमारी आस्था पर प्रहार किया उसे नया भारत स्वीकार नहीं कर सकता
- बहराइच में महाराजा सुहेलदेव का विजय स्मारक भी बनकर तैयार हो गया है

मुख्यमंत्री बहराइच में तहसील मिर्हीपुरवा (मोतीपुर) के मुख्य भवन के साथ ही आवासीय भवनों का उद्घाटन करने पहुंचे थे। तहसील का मुख्य और आवासीय भवन 845.19 लाख की लागत से 2,138 वर्ग मीटर में निर्मित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा यह बहराइच वही ऐतिहासिक भूमि है जहां पर एक विदेशी आक्रांता को धूल धुवरित करते हुए महाराजा सुहेलदेव ने भारत की विजय पताका को फहराया था। महाराज सुहेलदेव ने विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ जिस शौर्य और पराक्रम का



परिचय दिया उसी की परिणति थी कि 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की दुस्साहस नहीं कर पाया था। इस पावन धरा बहराइच को उसकी पहचान से वंचित करने का प्रयास हुआ था।

मुख्यमंत्री बोले कि अनंत संभावनाओं को समेटे यह जनपद बहराइच घाघरा और सरयू नदी के तट पर

स्थित है। खेती किसानों के साथ यहां पर वन्य जीव अभ्यारण भी है और अब तो बहराइच में मेडिकल कॉलेज भी बन गया है और महाराजा सुहेलदेव का विजय स्मारक भी बनकर तैयार हो गया है। यह वही जनपद है जो पहले अव्यवस्था और अराजकता का शिकार हुआ करता था। आज बहराइच में कोई अव्यवस्था नहीं फैला सकता।

युवा शक्ति से आत्मनिर्भर बनेगा उत्तर प्रदेश : योगी

आशीष पाण्डेय/दिव्य भारत
गोंडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को देवीपाटन मंडल के 1,423 युवा उद्यमियों को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम युवा) के तहत 55

- सीएम योगी ने देवीपाटन मंडल के 1,423 युवा उद्यमियों को बांटे 55 करोड़ रुपये के ऋण
- भ्रष्टाचार पर सख्त सीएम योगी बोले-लोन दिलाने के नाम पर ठगी बर्दाश्त नहीं
- डबल इंजन सरकार युवा उद्यमियों के आर्थिक स्वावलंबन में सहभागी बन रही है



योगी ने कहा कि अगर युवा ऊर्जा को सही दिशा में अवसर मिले, तो उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति से ही उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार युवा उद्यमियों के आर्थिक स्वावलंबन में सहभागी बन रही है। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र की ताकत उसकी युवा प्रतिभा, ऊर्जा और अनुशासन से मापी जाती है। जहां युवाओं को अवसर मिलते हैं, वहां कोई ताकत उस देश का बाल भी बांका नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान के तहत 3 लाख से अधिक युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें से 32,700 से

अधिक युवा उद्यमियों को ऋण स्वीकृत हो चुका है। सीएम योगी ने बताया कि आने वाले 25, 26 और 27 मार्च को हर जनपद में होने वाले तीन दिवसीय मेले में और अधिक युवाओं को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। उन्होंने युवाओं को सलाह दी कि वे लोन के कार्य की ट्रेनिंग लें, ताकि वे सफल उद्यमी बन सकें। पहली बार 5 लाख तक का लोन मिलने के बाद अगली बार 10 लाख तक की सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो युवा

कल तक रोजगार के लिए भटकता था, वह अब उद्यमी बनकर जनपद और प्रदेश को आगे बढ़ाएगा।

सीएम योगी ने कहा कि युवा शक्ति के स्वावलंबन से उत्तर प्रदेश और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। उन्होंने 1,423 युवाओं को ऋण वितरण पर बधाई दी और 25-27 मार्च को होने वाले मेले में अन्य युवाओं को भी लाभान्वित करने का भरोसा दिलाया। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को अमृत महोत्सव वर्ष में आप युवा ही साकार करेंगे। उन्होंने युवाओं से धैर्य और इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया, ताकि वे उत्तर प्रदेश को देश का प्रगति इंजन बना सकें।

खबर का असर : एसपी ऑफिस से हटवाया गया बोर्ड

दिव्य भारत संवाददाता
प्रतापगढ़। दिव्य भारत की खबर का जोरदार असर हुआ है, यातायात विभाग के द्वारा कुछ वर्ष पहले एसपी ऑफिस में यातायात माह नवंबर को लेकर एक बोर्ड लगाया गया था जिसमें उस समय के एसपी सतपाल अंतिल, एसपी पूर्वी विद्यासागर मिश्रा, एसपी पश्चिमी रोहित मिश्रा जैसे अधिकारियों के नाम के बोर्ड एसपी कार्यालय में लगावाया गया था। लेकिन इन अधिकारियों के अन्य जिलों में तबादला होने के बावजूद यह बोर्ड एसपी ऑफिस में टंगा रहा। जब इस खबर को प्रमुखता से दैनिक दिव्य भारत अखबार ने प्रकाशित किया तो अधिकारियों के द्वारा इस खबर को संज्ञान में लेकर एसपी ऑफिस में लगे बोर्ड को हटवा लिया गया है।

नहीं बदला तो एसपी कार्यालय में लगा यातायात विभाग का बोर्ड

धर्मेन्द्र श्रीवास्तव/दिव्य भारत

प्रतापगढ़। जिले में यातायात विभाग सिर्फ हर चौराहे पर लोगों के चलाने काटने में जुटे रहती है और गहर के अंदर जाम का जाम करना लोगों को झेलना पड़ता है। लोगों द्वारा उन पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि वो चलाने के नाम पर लोगों से धनवसूली किया जाता है। वहीं यातायात विभाग का एक और हैरतअंगेज मामला सामने आया है कि एसपी कार्यालय में यातायात विभाग के द्वारा यातायात माह नवंबर का एक बोर्ड लगाया गया है। जो कि काफी पहले का है जिसमें एसपी सतपाल अंतिल और एसपी पूर्वी विद्यासागर मिश्रा, एसपी पश्चिमी रोहित मिश्रा जैसे अधिकारियों के नाम के बोर्ड एसपी कार्यालय में लगावाया गया था। लेकिन इन अधिकारियों के अन्य जिलों में तबादला होने के बावजूद यह बोर्ड एसपी ऑफिस में टंगा रहा। जब इस खबर को प्रमुखता से दैनिक दिव्य भारत अखबार ने प्रकाशित किया तो अधिकारियों के द्वारा इस खबर को संज्ञान में लेकर एसपी ऑफिस में लगे बोर्ड को हटवा लिया गया है।

एसपी कार्यालय में लगे बोर्ड पर नहीं किसी अधिकारी को नजर



केटीक नगर में हो यह बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन किसी भी अधिकारी को नजर इस बोर्ड पर नहीं पड़ता। पुलिस कार्यालय में लगा यह बोर्ड लोगों के लिए मजाक का शिराना बन गया है, हर कोई इस बोर्ड को देखकर मजाक उड़ाने में पीछे नहीं हटता। क्या यह बोर्ड ऐसे ही लगा होगा और इसे देखकर लोग मजाक उड़ाने लगे, वही सोचा हुआ है यातायात विभाग अब देखना चाह है कि यातायात विभाग कब कुंभकर्ण नील से जागता और यह बोर्ड कब हटवा जाएगा।

पत्थरबाज भूत या शरारती तत्वों से परेशान ग्रामीण

धर्मेन्द्र श्रीवास्तव/दिव्य भारत

प्रतापगढ़/पट्टी। रात को जब सब सो जाते हैं तब अचानक घरों पर पत्थर फेंकना शुरू हो जाता है। यह पत्थर कौन फेंकता है कोई समझ नहीं पा रहा है, आखिर पत्थर फेंकने के बाद वह कैसे गायब हो जाता है। वह भूत है या कोई शरारती तत्व हर किसी के समझ के बाहर हो गया है। मामला है पट्टी कोतवाली एरिया के डडवा गांव में कुछ दिनों से रात होते ही आसमान से पत्थरों की बरसात शुरू होने लगती है। फेंके गये पत्थरों से कई ग्रामीण घायल भी हो चुके हैं, वहीं तो कई ग्रामीण ऐसे हैं जिनके मकान और सामान क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

चौकाने वाली बात यह है कि पूरे गांव वालों को पता नहीं चल पा रहा है कि पत्थर भूत फेंक रहा है या कोई इंसान, पत्थर कहाँ से आता है और फेंकने वाला कैसे गायब हो जाता है हर किसी के समझ से परे हो गया है। खोजबीन करने के बाद भी कोई नहीं मिलता है जिससे ग्रामीण बहुत दहशत में हैं। मिली जानकारी के अनुसार तकरीबन पंद्रह दिनों से लगातार पत्थर फेंका जा रहा है। शाम सात बजते

ही पत्थरों की बरसात होना शुरू हो जाता है और रात 11 बजे तक लगातार पत्थरबाजी होती रहती है। इस पत्थरबाजी में एक महिला के सर पर पत्थर लगने से घायल हो चुकी हैं, घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आश्चर्यजनक बात यह है कि जब पत्थरबाजी होती है तो दस से बारह युवाओं की टोली पत्थरबाजों को दूढ़े निकल जाती है, लेकिन बीते दस दिनों में युवाओं को न तो भूत ही मिला और न ही इंसान। ऐसे में इस आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना को कई लोग इसे भूत-प्रेत की हरकत भी बता रहे हैं तो कुछ इसे शरारती तत्वों की हरकत बता रहे हैं। गांव के ही रामदुलार यादव, भूलन गुप्ता, बबलू गौतम, मंजीत यादव, राजकुमार यादव ने पत्थरबाजी की घटना को लेकर पट्टी कोतवाली में तहरीर दी है। दिये गए शिकायतीपत्र में बताया है कि किस तरह पत्थरबाजी से सभी भय के माहौल में जी रहे हैं। वहीं घरों में पत्थर गिरने से घर तो क्षतिग्रस्त हो ही रहे हैं, साथ ही लोगों को भी चोटें आ रही हैं। इस मामले में पट्टी पुलिस तहरीर लेकर जांच में जुट गई है।

कृषि-खाद्य क्षेत्र में नियामक अनुपालन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम का सफल समापन

सुजीत चतुर्वेदी/दिव्य भारत

झांसी। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी में कृषि-खाद्य क्षेत्र में नियामक अनुपालन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार एवं नीति आयोग, भारत सरकार का वित्तीय सहयोग प्राप्त था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण और नियामक अनुपालन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता बढ़ाना और खाद्य परीक्षण में आधुनिक विश्लेषणात्मक उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम में देशभर से प्रतिष्ठित विज्ञानवेत्ता, शोधकर्ता, शिक्षाविद एवं विषय-विशेषज्ञ शामिल हुए, इन्होंने अपने बहुमूल्य विचार और विशेषज्ञता साझा की। इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा एवं मानकों के अनुपालन, नवीनतम परीक्षण तकनीकों, सैफेलिंग विधियों, डेटा प्रबंधन, प्रयोगशाला सुरक्षा एवं अपशिष्ट निपटान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के समापन सत्र में डॉ. योगेश्वर सिंह ने सभी प्रतिभागियों, विशेषज्ञों, आयोजकों एवं विश्वविद्यालय प्रशासन को इस आयोजन को सफल बनाने में उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि



यह प्रशिक्षण कार्यक्रम खाद्य परीक्षण और सुरक्षा मानकों को समझ विकसित करने में अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ है। इस सफल आयोजन के बाद, विश्वविद्यालय प्रशासन ने भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन का संकल्प लिया, जिससे खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को और अधिक बढ़ावा मिल सके। इस कार्यक्रम से प्रतिभागियों को न केवल सैद्धांतिक ज्ञान मिला, बल्कि उन्हें व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त हुआ, जिसे वे अपने संबंधित क्षेत्रों में लागू कर सकते हैं।

इस दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन अत्यंत सफलतापूर्वक हुआ और यह खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

संक्षिप्त समाचार

दरोगा और वन विभाग की मिलीभगत से कट रहे हैं हरे पेड़

धर्मेन्द्र श्रीवास्तव/दिव्य भारत संवाददाता

प्रतापगढ़। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पेड़ लगवाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। मुख्यमंत्री से लेकर हर अधिकारी पेड़ लगा रहा है लेकिन दिलीपपुर थाने में तैनात दरोगा राजेंद्र कुमार वर्मा और वन विभाग की मिलीभगत से वनमाफिया के द्वारा खुलेआम हरे पेड़ों को काट दिया जा रहा है। हरे पेड़ों को कटवाने के एजेंड में दरोगा साहब और वनविभाग के लोग रुपए ले रहे हैं। वनमाफिया और दिलीपपुर थाने में तैनात दरोगा राजेंद्र कुमार वर्मा का एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वनमाफिया से पैसा की लेनेदने की बात हो रही है। जिसमें दरोगा साहब कह रहे हैं कि पंद्रह सौ रुपए दो लेकिन बारह सौ रुपए में सौदा तय होता है। क्योंकि वनमाफिया के द्वारा फोन पर कहा जा रहा था उन्होंने वनविभाग के लोगों को भी रुपये दिए क्योंकि वह मौके पर पहुंच गये थे।

रामनवमी से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री

दिव्य भारत संवाददाता

अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को एकदिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचेंगे। वह तकरीबन पांच घंटे तक रामनगरी में रहेंगे। दर्शन-पूजन के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और अयोध्या के विकास के साथ-साथ रामनवमी की तैयारियों को लेकर अफसरों के साथ मंथन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह करीब साढ़े नौ बजे अयोध्या पहुंचेंगे। वे सबसे पहले हनुमानगढ़ी, फिर श्रीरामलाला के दर्शन पूजन करेंगे। इसके उपरांत राजसदन में लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल होंगे। इसके बाद रामकथा पार्क में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिट कार्ड कैम्प में शामिल होकर प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। यहां से आवुक्त कार्यालय सभागार पहुंचकर समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद प्रयागराज मार्ग स्थित लक्ष्मी ग्रुप ऑफ कम्पनीज के कॉलेजियल प्लॉट का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से लखनऊ प्रस्थान कर जाएंगे।

दुष्कर्म मामले में पीड़िता के बयान दर्ज, पूरे बाजार में सुरक्षा का सख्त पहरा

हाथरस, (हि.स.)। बिसावर में सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म की घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने पूरे बाजार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पीड़िता के पिता के मुताबिक, आरोपी अमन खान ने चॉकलेट दिलाने का सालख देकर उनकी बेटी को अकेले में ले गया। आरोपी ने बच्ची को लालच बेहमी से मारपीट की। उसने बच्ची को कई बार जमीन पर पटक कर और घूंसे मारकर उसके तीन दांत तोड़ दिए। आरोपी ने बच्ची के होंठ और गाल को दांतों से काटा, जिससे उन जगहों पर सूजन आ गई है। घटना के समय पीड़िता के साथ उसकी चचेरी बहन भी थी। आरोपी ने चचेरी बहन को धक्का देकर गिराया और बच्ची को अकेला पाकर उसे बंद कर लिया। चचेरी बहन ने घर जाकर परिवार को सूचना दी। पीड़िता के पिता का कहना है कि अगर वे समय पर नहीं पहुंचते तो आरोपी बच्ची को मारकर तालाब में फेंक सकता था।

प्रदेश के युवाओं की पसंद बनी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, लक्ष्य से अधिक युवाओं ने किया आवेदन

आशीष पाण्डेय/दिव्य भारत

लखनऊ। योगी सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना प्रदेश के युवाओं की पहली पसंद बन गयी है। अपने शुभारंभ के महज 55 दिनों में प्रदेश के डेढ़ लाख से अधिक नौजवानों ने योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन किया, जबकि योगी सरकार ने योजना के तहत पहले चरण में एक लाख युवाओं को लोन देने का लक्ष्य रखा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मॉनिटरिंग और पारदर्शिता का असर है कि करीब दो माह में ही विभिन्न बैंकों ने 32 हजार से अधिक युवाओं को लोन दे दी है। इस योजना के तहत लोन वितरण में श्रावस्ती प्रदेश में पहले स्थान पर है। श्रावस्ती के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप जिले में योजना का लाभ देने के लिए जगह-जगह शिबिर लगाए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को योजना का लाभ दिया जा सके। जिलाधिकारी ने बताया कि योजना के तहत पहले चरण में जिले के 700 युवाओं को लोन वितरित करने का लक्ष्य रखा गया था। जिसके सापेक्ष 2190 युवाओं ने आवेदन किया।

इसमें से 17,770 युवाओं को लोन की राशि का वितरण भी किया जा चुका है। यह योजना न केवल युवाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनने के अवसर दे रही है, बल्कि प्रदेश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत लोन वितरण में श्रावस्ती प्रदेश में पहले स्थान पर है। श्रावस्ती के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप जिले में योजना का लाभ देने के लिए जगह-जगह शिबिर लगाए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को योजना का लाभ दिया जा सके। जिलाधिकारी ने बताया कि योजना के तहत पहले चरण में जिले के 700 युवाओं को लोन वितरित करने का लक्ष्य रखा गया था। जिसके सापेक्ष 2190 युवाओं ने आवेदन किया।

- योगी सरकार ने 1 लाख युवाओं को लोन देने का रखा था लक्ष्य, 1 लाख 51 हजार से अधिक आए आवेदन
- योजना शुभारंभ के महज 55 दिनों में बैंकों ने दी 32,757 युवाओं को लोन देने की हरी झंडी
- 62 प्रतिशत आवेदकों को लोन का डिस्ट्रीब्यूशन कर, श्रावस्ती रहा प्रदेश में पहले स्थान पर
- महाराजगंज और रामपुर जिले लोन वितरण करने के क्रम में रहे प्रदेश में दूसरे और तीसरे स्थान पर
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना प्रदेश के युवाओं को बना रही आत्मनिर्भर

इसमें से 650 युवाओं को लोन देने के लिए बैंकों ने अपनी स्वीकृति दे दी है जबकि 436 युवाओं को लोन की राशि वितरित भी की जा चुकी है। जो कि लक्ष्य का 62.29 प्रतिशत है। इसी के साथ श्रावस्ती पूरे प्रदेश में सबसे अधिक योजना का लाभ देने के क्रम में पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर है।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत

प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में श्रावस्ती के बाद महाराजगंज और रामपुर इस सूची में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। जहां जिले के लक्ष्य के 60.40% और 51.90% युवाओं को लोन राशि वितरित की जा चुकी है। इसके अलावा, अंबेडकर नगर और ललितपुर लोन वितरण में चौथे और पांचवें स्थान पर रहे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में योजना की प्रगति की बात करें तो अम्बेडकर नगर, ललितपुर, कन्नौज, रायबरेली और बहराइच जैसे जिलों में भी लोन वितरण में उल्लेखनीय सफलता देखी गई है।

यह दशता है कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी युवाओं में इस योजना के प्रति रुचि बढ़ रही है और वे अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार हैं। स्पष्ट संकेत है कि योगी सरकार की यह पहल प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ प्रदेश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी।